सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 84 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, मंगलवार 06 जनवरी 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

पूर्व केंद्रीय मंत्री कलमाड़ी का निधन, एयरफोर्स में पायलट थे

पुणे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 81 साल के थे। कलमाड़ी को पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने मंगलवार सुबह करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर दोपहर 2 बजे तक कलमाड़ी हाउस एरंडवणे में रखा जाएगा। अंतिम संस्कार दोपहर 3.30 बजे वैकुंठ श्मशान पुणे में होगा। कलमाड़ी पुणे लोकसभा सीट से 3 बार सांसद चुने गए।

8 जनवरी को रायपुर आएंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट

रायपुर। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 8 जनवरी को एक दिन के दौरे पर रायपुर आने वाले हैं। पार्टी के मुताबिक, इस दौरान वे प्रदेशभर में मनरेगा को लेकर चल रहे आंदोलन की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही हाल ही में नियुक्त किए गए जिलाध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि, सचिन पायलट इस दौरे के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों पर भी फोकस करेंगे। नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की भूमिका, जिम्मेदारियों और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होने की संभावना है।

सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती, प्रदूषण के कारण खांसी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सोमवार शाम को भर्ती कराया गया था। उनकी हालत स्थिर है और उन्हें छाती रोग विशेषज्ञ की निगरानी में रखा गया है। सोनिया गांधी को लंबे समय से खांसी की समस्या है। खासकर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। सोनिया गांधी दिसंबर 2025 में 79 साल की हो चुकी हैं।

माण्ड व्यपवर्तन योजना के कार्यों के लिए 52.58 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा रायगढ़ जिले की माण्ड व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य एवं नहरों का आधुनिकरण, उन्नयन, जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य के लिए 52 करोड़ 58 लाख 30 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना से रूपांकित सिंचाई क्षेत्र 13118 हेक्टेयर में 2240 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के कार्य पूर्ण कराने मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

सरकारी स्कूल में आवारा कुत्ते का आतंक, चार बच्चे घायल

बिलासपुर। पीएमश्री स्कूल खमतराई के बाद अब सकरी क्षेत्र के एक और सरकारी स्कूल में आवारा कुत्ते का आतंक देखने को मिला है। सोमवार को स्कूल में नियमित कक्षाएं चल रही थीं। इसी दौरान एक आवारा कुत्ता स्कूल परिसर में घुस आया और आठवीं कक्षा की छात्रा मोना यादव के पैरों में दांत गड़ा दिए। इसके बाद यादव मोहल्ला निवासी तमन्ना साहू और सूरज पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते की आक्रामकता देख शिक्षकों ने तुरंत बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

शिक्षकों की मांगों को लेकर जेडी कार्यालय का घेराव

दुर्ग। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने प्रांताध्यक्ष रविंद्र राठौर के नेतृत्व में जेडी कार्यालय दुर्ग का घेराव किया। इस दौरान फेडरेशन ने मिडिल स्कूल हेडमास्टर पद पर पदोन्नति, उच्च वर्ग शिक्षक पद पर पदोन्नति तथा उच्च परीक्षा की अनुमति से संबंधित आदेश जारी करने की प्रमुख मांगें जेडी के समक्ष रखीं।

बिहान योजना से दिल्ली का सफर : गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होंगी 'लखपति दीदी-लता साहू'

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत बिहान योजना आज सकारात्मक बदलाव की मिसाल बन चुकी है। इसी योजना से जुड़कर कबीरधाम की लता साहू ने अपने आत्मविश्वास, परिश्रम और महिला स्व-सहायता समूह की ताकत से सफलता की प्रेरक कहानी लिखी है। लता साहू की आर्थिक स्थिति पहले सामान्य थी। सीमित आय के कारण परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो जाता था। ऐसे समय में उन्होंने महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ने का निर्णय लिया, जो उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ।

टेंट एवं कैटरिंग व्यवसाय

समूह से जुड़ने के बाद उन्हें न केवल बचत की आदत पड़ी, बल्कि समूह के माध्यम से आजीविका ऋण भी प्राप्त हुआ। इस ऋण राशि का सदुपयोग करते हुए लता साहू ने टेंट एवं कैटरिंग व्यवसाय की शुरुआत की। यह व्यवसाय धीरे-धीरे उनकी आय का स्थायी और मजबूत साधन बन गया। समय पर कार्य, गुणवत्ता और निरंतर मेहनत के बल पर उनका व्यवसाय लगातार आगे बढ़ता गया, जिससे उनकी मासिक एवं वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आज लता साहू लखपति दीदी के रूप में पहचानी जाती हैं।

26 जनवरी को होंगी सम्मानित

लता साहू की सफलता ने महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ी अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया है। आज कई महिलाएं उन्हें आदर्श मानकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लता साहू कहती हैं कि बिहान योजना ने मुझे आत्मविश्वास दिया। समूह की ताकत और सही मार्गदर्शन से मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूं। आज लता साहू पूरे कबीरधाम जिले के लिए प्रेरणा और मिसाल बन चुकी हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा, जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे जिले के लिए गौरव का विषय है।

सुकमा जिले के तीन स्वास्थ्य केंद्रों को मिला राष्ट्रीय 'NQAS' सर्टिफिकेट

बुड़दी, गगपल्ली और किस्टाराम के अस्पतालों को केंद्र सरकार से मिली मान्यता

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। सुकमा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के निरंतर प्रयासों ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। सुकमा ज़िले के घोर नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुड़दी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर गगपल्ली और आयुष्मान आरोग्य मंदिर किस्टाराम को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स(NQAS) प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। यह उपलब्धि केवल एक सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रशासन 'अंतिम व्यक्ति' तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने के अपने संकल्प को सिद्ध कर रहा है।

सुकमा जैसे संवेदनशील ज़िले में, जहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ और सुरक्षा की चुनौतियाँ अक्सर बाधा बनती हैं, वहां के स्वास्थ्य केंद्रों का राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। इन केंद्रों ने सेवा प्रावधान, मरीज के अधिकार और संक्रमण नियंत्रण जैसे 8 कड़े मानकों पर 70 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी उत्कृष्टता साबित की है। ज़िला प्रशासन ने इन केंद्रों में बुनियादी ढाँचे और नैदानिक देखभाल को बेहतर बनाने के लिए नियद नेल्लानार के अंतर्गत विशेष कार्ययोजना तैयार की गई थी। दुर्गम क्षेत्रों में दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। अस्पतालों में स्वच्छता और बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी गई। मरीजों को न केवल उपचार मिले, बल्कि उनके अधिकारों और सम्मान का भी पूरा ध्यान रखा गया।

क्या है NQAS और इससे क्या बदलेगा

NQAS सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बनाया गया एक सख्त फ्रेमवर्क है। इस प्रमाणन के बाद अब इन केंद्रों को भारत सरकार की ओर से वित्तीय प्रोत्साहन भी मिलेगा। इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य सुविधाओं के और अधिक विस्तार और रखरखाव के लिए किया जाएगा, जिससे भविष्य में स्थानीय ग्रामीणों को और भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

कलेक्टर ने उपलब्धि को बताया ऐतिहासिक

कलेक्टर अमित कुमार ने बताया कि सुकमा जिले के 3 स्वास्थ्य केंद्रों को हक़्क़र सर्टिफिकेट मिलना जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों का राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना यह दर्शाता है कि प्रशासन की प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए विकास को गति देना है।

भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : सीएम साय

■ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ली उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर प्रदेश में आयोजित हो रही विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की व्यापक समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्णत: पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराना है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि युवा कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इसलिए शासन की प्रतिबद्धता है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी भर्ती परीक्षाएँ पारदर्शी ढंग से आयोजित की जाएँ तथा परीक्षा प्रणाली को वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप और अधिक सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता स्वीकार्य नहीं होगी। निष्पक्षता सुनिश्चित करने सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता पर कोई प्रश्नचिह्न न लगे, इसके लिए पारदर्शिता बढ़ाने संबंधी सभी उपायों पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। इससे राज्य में भर्ती प्रणाली अधिक सरल, न्यायोचित और समयबद्ध बनेगी। बैठक में पुलिस बल सहित विभिन्न विभागों में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की गई और चयन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्लै, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम आदि उपस्थित रहे।

चिल्फी में अवैध अक्सा मस्जिद पर चला बुलडोजर

श्रीकंचनपथ न्यूज

कवर्धा। चिल्फी जिसे मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है पर्यटन और प्रदेश व कई जिलों को जोडने वाले केंद्र बिंदु चिल्फी मे 2019 में पूर्ववर्ती कांग्रेस कार्यकाल में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने वर्तमान में गृह मंत्री मान विजय शर्मा से शिकायत की थी। शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम के साथ पुलिस प्रशासन की उपस्थिति मे अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया।

मंडल भाजपा के उपाध्यक्ष प्रकाश धारवैया ने बयान जारी कर कहा उपमुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा के पहल से प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटाए जाने के बाद अब क्षेत्र में आदिवासी सम्मान और सांस्कृतिक पहचान को लेकर इसी स्थान पर भगवान बिरसा मुंडा का भव्य मूर्ति का स्थापना जल्द किया जाएगा स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं बनी।

छत्तीसगढ़ में कोहरा-शीतलहर का डबल अटैक, अंबिकापुर 4.8 डिग्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर बढ़ गया है और उत्तरी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। जनवरी आते ही ठंड ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में हालात ऐसे हैं कि सुबह घर से निकलते ही सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। ठंडी हवाओं की वजह से रात और सुबह के समय ठिठुरन और बढ़ेगी। लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं और गर्म कपड़ों की मांग भी अचानक बढ़ गई है।

छोटे भाई ने सोते हुए बड़े को उतारा मौत के घाट

श्रीकंचनपथ न्यूज

जगदलपुर। गीदम थाना क्षेत्र के ग्राम कमलापदर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां छोटे भाई ने मामूली कहासुनी के बाद अपने बड़े भाई की खोटला से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी छोटा भाई मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

मामले की जानकारी देते हुए गीदम थाना प्रभारी विजय पटेल ने बताया कि ग्राम कमलापदर निवासी 45 वर्षीय मंगलू कुंजाम बीती रात अपने छोटे भाई पिंगडू उर्फ रवि कुंजाम के साथ किसी बात को लेकर बहस कर रहा था। यह कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पिता को दोनों भाइयों को अलग करना पड़ा। छोटे भाई को बड़े भाई की बात इतनी बुरी लगी कि उसने देर रात को कमरे में सो रहे मंगलू पर हमला बोल दिया। पिंगडू ने धान कूटने वाले खोटला को उठाया और सीधे अपने बड़े भाई के सीने पर वार कर दिया। इस खौफनाक हमले में मंगलू कुंजाम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

घटना को अंजाम देने के बाद छोटा भाई पिंगडू उर्फरवि कुंजाम घटना स्थल से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश के लिए इलाके में नाकेबंदी कर दी है।

रेप के बाद नाबालिग को कुल्हाड़ी से काटा

श्रीकंचनपथ न्यूज

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 11 साल की नाबालिग से रेप-मर्डर का मामला सामने आया है। 31 दिसंबर की शाम आरोपी युवक नाबालिग को अपने साथ खेत ले गया, वहां उसने दुष्कर्म किया फिर लड़की किसी को बता ना दें इस डर से खेत में रखे कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया। मामला जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र का है।

आरोपी संजू कुमेटी (22 साल) ने हत्या के बाद शव को गांव के ही खेत में फेंक दिया था। 4 दिन बाद गांव वालों ने लाश देखी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, नाबालिग नारायणपुर जिले के एक गांव की रहने वाली थी। लड़की के घर वाले सल्फी बेचते थे, आरोपी संजू कुमेटी अक्सर घर में सल्फी लेने आया करता था। इस दौरान ही लड़की से उसकी पहचान हुई थी। 31 दिसंबर से नाबालिग घर से लापता थी। परिवार के सदस्य उसे यहां-वहां ढूंढते रहे। उसका पता नहीं चला। 4 जनवरी को गांव के ही एक खेत में नाबालिग की लाश मिली। गांव वालों ने इसकी जानकारी परिजनों व पुलिस को दी। पीएम रिपोर्ट में रेप की बात सामने आई। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

शादी से पहले मेडिकल टेस्ट के मायने

कुछ बीमारियां हैं जो आनुवांशिक होती हैं। इन्हें फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका है प्री-मैरिटल काउंसलिंग। सभी देश जानते हैं पर कुछ खास कर नहीं पाते। भारत में गांव-गांव में आनुवांशिक बीमारियों की रोकथाम के लिए शिविर लगाकर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। पर स्थिति पर कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। अब एक मुस्लिम देश की सरकार ने इस दिशा में ठोस प्रयास किया है। ओमान ने शादी करने वाले सभी कपल्स के लिए प्री-मैरिटल मेडिकल टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। सुल्तान हैथम बिन तारिक की ओर से जारी रॉयल डिक्री के द्वारा इसे लागू किया गया है। अब शादी से पहले दोनों पार्टनर को यह टेस्ट पास करना जरूरी है, चाहे शादी ओमान के अंदर हो या बाहर। अगर एक पार्टनर गैर-ओमानी भी है तो भी यह नियम लागू होगा। नए नियम के तहत सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की जांच की जाएगी। यहां की लगभग 10 फीसद आबादी इस स्वास्र। समस्या का सामना कर रही है। इसके अलावा ब्लड सैंपल से हेपेटाइटिस-बी तथा सी की भी जांच हो जाएगी। साथ ही एचआईवी/एड्स की भी जांच हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी सिकल सेल वाले मरीजों की संख्या लगभग 10 फीसदी है। कुछ समाजों में यह आकड़ा 30 फीसदी तक है। सही वैवाहिक प्लानिंग से ही इस संख्या को कम किया जा सकता है। कुछ समाजों में जागरूकता भी आई है पर इसकी गंभीरता को लेकर लोग अब भी उतने सचेत नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ में थैलेसीमिया के सटीक आंकड़े नहीं मिलते पर 15,000 से अधिक बच्चे इस बीमारी से पीड़ित बताए जाते हैं। इन बच्चों को उनके पूरे जीवन काल में लगातार रक्त चढ़ाना पड़ता है। चिंता की बात यह भी है कि एससी/एसटी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे ज्यादा पीड़ित हैं जिनके पास इसका खर्च उठाने का सामर्थ भी नहीं होता। विशेष रूप से जनजातीय समुदायों में अल्फा-थैलेसीमिया लगभग दो तिहाई आबादी में देखी गई है। प्री-मैरिटल मेडिकल काउंसलिंग को अनिवार्य कर इसकी पूरी तरह रोकथाम तो शायद न हो पर एक प्रभावी नियंत्रण तो हासिल किया ही जा सकता है।

डिप्टी सीएम शर्मा ने स्वर्ण पदक विजेता रिया का किया सम्मान

रायपुर। बिहार की राजधानी पटना में 25 से 29 दिसंबर तक आयोजित साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हाँसिल किया। इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका सहित चार देशों की टीमों ने भाग लिया था। इस चैंपियनशिप में भारत की विजेता टीम का हिस्सा बनकर देश और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली कवर्धा की होनहार खिलाड़ी रिया तिवारी का उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सम्मान किया।

संपादकीय

पाकिस्तान को लेकर हमारी प्रतिक्रियाएं अब बदल रही हैं

भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में अस्थिरता कायम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही दोनों में कोई बड़ी लड़ाई, कूटनीतिक संबंधों में नाटकीय विच्छेद या लंबा सैन्य तनाव नहीं हुआ है, फिर भी रणनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। जो नियम कभी संकट के वक्त लागू होते थे- वे बदल रहे हैं। दोनों देश इस नई वास्तविकता के प्रति खुद को ढाल भी रहे हैं।

भारत के लिए वही सवाल आज भी कायम है कि पाकिस्तान प्रायोजित हिंसा अगली बार बर्दाश्त से बाहर हुई तो हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे? हाल में दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह षड्यंत्र और व्यापक रूप ले सकता था, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। ऐसे में उपरोक्त सवाल का जवाब घोषणाओं नहीं, हालिया अनुभवों और पाकिस्तान में हो रहे बदलावों में छिपा है। इसे समझने के लिए ऑपरेशन सिंदूर सबसे अहम संदर्भ है। इसने हमारे माइंडसेट को उजागर किया। भारत ने दिखाया कि वह परमाणु सीमा में रहते हुए संतुलित सैन्य बल इस्तेमाल करने को तैयार है। इसमें राजनीतिक मंजूरी जल्द मिल जाती है और लक्ष्य भी सीमित होते हैं। संदेश यह था कि आतंकवाद के जवाब में भारत अब महज संयम पर ही निर्भर नहीं रहेगा।

> “ उतना ही महत्वपूर्ण यह जानना भी है कि ऑपरेशन सिंदूर ने कौन-से संकेत नहीं दिए। भारत छोटे ऑपरेशन, तय समय सीमा और सैन्य तनाव में बढ़ोतरी के ऐसे तरीकों में नहीं बंधा, जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता हो। कहीं भी यह नहीं कहा गया कि भविष्य में सैन्य कार्रवाई प्रतीकात्मक या निश्चित अवधि वाली होगी। यह अस्पष्टता भी मायने रखती है। यदि विरोधी पहले ही जान ले कि जवाबी कार्रवाई कैसे, कब और कितनी देर में होगी तो वह उसे अपने आकलन में शामिल कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के जानबूझकर ऐसे सवालों को अनुत्तरित छोड़ा गया।

उतना ही महत्वपूर्ण यह जानना भी है कि ऑपरेशन सिंदूर ने कौन-से संकेत नहीं दिए। भारत छोटे ऑपरेशन, तय समय सीमा और सैन्य तनाव में बढ़ोतरी के ऐसे तरीकों में नहीं बंधा, जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता हो। कहीं भी यह नहीं कहा गया कि भविष्य में सैन्य कार्रवाई प्रतीकात्मक या निश्चित अवधि वाली होगी। यह अस्पष्टता भी मायने रखती है। यदि विरोधी पहले ही जान ले कि जवाबी कार्रवाई कैसे, कब और कितनी देर में होगी तो वह उसे अपने आकलन में शामिल कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जानबूझकर ऐसे सवालों को अनुत्तरित छोड़ा गया था। जब भारत प्रतिक्रिया को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर रहा था तो पाकिस्तान के भीतर भी बदलाव चल रहे थे। पाकिस्तानी संविधान में प्रस्तावित 27वां संशोधन महज एक कानूनी बदलाव नहीं है। सेना प्रमुख को चीफऑफडिफेंस फोर्सेस बनाना, सेना के सामूहिक ढांचे को समाप्त करना और परमाणु कमान को पूरी तरह सैन्य नियंत्रण में लाना- यह बताता है कि सारा नियंत्रण अब शीर्ष पर केंद्रित हो रहा है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह पाकिस्तान के इन संकेतों का जवाब कैसे दे, जिससे तनाव भी ना बढ़े और यह भी नहीं दिखे कि वह चुपचाप बैठा है। परमाणु धमकियों के कारण यदि पारंपरिक और मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी रोक दी जाएं तो यह पाकिस्तान की प्रॉक्सी युद्ध की रणनीति को और प्रभावकारी बनाता है। इसलिए प्रतिरोध का मतलब है कि भारत दिखाए परमाणु हमले की धमकियां उसके विकल्पों पर पूर्ण विराम नहीं लगातीं। इसका मतलब अनावश्यक तनाव बढ़ाना नहीं, कार्रवाई की स्वतंत्रता बनाए रखना है। कश्मीर इस पूरे बदलाव का केंद्र बना हुआ है। हाल के वर्षों में कश्मीर घाटी की तुलना में जम्मू, खासकर रजौरी, पुंछ और कठुआ में अधिक हिंसा हुई है। यह मायने रखता है। पाकिस्तान का सियासी नैरेटिव और उसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति जम्मू के बजाय कश्मीर के इर्द-गिर्द घूमती है। घाटी में लंबे समय की शांति उस मुद्दे पर पाकिस्तान की प्रासंगिकता घटाती है, जिसे वह अपनी पहचान का मूल मानता है। पहलगाम हमला इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह किसी सतत अभियान की शुरुआत से ज्यादा ऐसे वक्त में कश्मीर में फिर से मौजूदगी दिखाने का प्रयास लगता है, जब वहां पर्यटन, नागरिक गतिविधियां और सामान्य स्थिति की भावना मजबूत हो रही थी। इतिहास गवाह है कि जब भी पाकिस्तान को कश्मीर में अपनी प्रासंगिकता घटती महसूस हुई, उसने खुले टकराव के बजाय सीमित तौर पर व्यवधान पैदा करने वाली हरकतों का सहारा लिया।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसम्बर, 2023 तक देश की विभिन्न जेलों में 21,510 महिला कैदी और 1492 शिशु बन्द थे। छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपनी माताओं के साथ जेल में रहने की अनुमति है, यदि उनकी देखभाल के लिए बाहर कोई उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध न हो। शिशुओं के साथ उनकी 1318 माताओं में से 1049 विचाराधीन कैदी थी और शेष 249 महिलाएं दोष-सिद्ध महिलाएं थीं। देश की जेलों में महिला कैदियों की संख्या 4 प्रतिशत है। उनकी कैद मानवाधिकारों से जुड़ी अनेक चिन्ताएं उत्पन्न करती है, विशेषतया उनके बच्चों के सम्बन्ध में। महिला अपराधियों का कारावास न्याय-शास्त्र की दुविधा की ओर भी इशारा करता है कि क्या महिलाओं को पुरुषों के समान ही दण्ड प्रक्रिया और सुधारात्मक मानकों के अधीन रखा जाए।

महिला कैदियों हेतु लिंग-संवेदनशील सजा नीति बने

केपी सिंह

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने स्थापना दिवस पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'कारागार बंदियों के मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन किया। एक सत्र में महिला कैदियों और उनके बच्चों के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील जेल सुधार पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप उनके सार्थक पुनर्वास को सुनिश्चित करने वाली 'महिलाओं के लिए हिरासत में न्याय' पर राष्ट्रीय नीति बनाने पर जोर दिया।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसम्बर, 2023 तक देश की विभिन्न जेलों में 21,510 महिला कैदी और 1492 शिशु बन्द थे। छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपनी माताओं के साथ जेल में रहने की अनुमति है, यदि उनकी देखभाल के लिए बाहर कोई उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध न हो। शिशुओं के साथ उनकी 1318 माताओं में से 1049 विचाराधीन कैदी थी और शेष 249 महिलाएं दोष-सिद्ध महिलाएं थीं। देश की जेलों में महिला कैदियों की संख्या 4 प्रतिशत है। उनकी कैद मानवाधिकारों से जुड़ी अनेक चिन्ताएं उत्पन्न करती है, विशेषतया उनके बच्चों के सम्बन्ध में। महिला अपराधियों का कारावास न्याय-शास्त्र की दुविधा की ओर भी इशारा करता है कि क्या महिलाओं को पुरुषों के समान ही दण्ड प्रक्रिया और सुधारात्मक मानकों के अधीन रखा जाए।

महिलाओं का अपराध क्षणिक आवेश की परिणति होता है। महिला सौंदर्य, रचनात्मकता, देखभाल और प्रेम, इच्छा, समृद्धि और सृजन की प्रतिमूर्ति होती है और अपराध-प्रवृत्ति उसके स्वभाव में नहीं है। महिलाओं द्वारा अपराध करने के पीछे के कारणों और उद्देश्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि वे ऐसा मुख्य रूप से जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करती हैं, जब उनके पास अपने बच्चों और परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई और विकल्प नहीं बचता है। कभी-कभी, महिलाएं लैंगिक रूप से असंवेदनशील सामाजिक व्यवस्था और नारीत्व को ठेस पहुंचाने वाले मानदण्डों के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए भी कानून तोड़ने पर मजबूर होती हैं। अक्सर, महिला अपराधी अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कथित पारिवारिक सम्मान की रक्षा और विरोधियों से बदला लेने के लिए अपराधों में संलिप्त हो जाया करती हैं। लगभग हर स्थिति में, महिला अपराधी परिस्थितियों की शिकार होती हैं। उन्हें अपने दोषपूर्ण पालन-पोषण और प्रतिकूल पारिवारिक वातावरण की कीमत चुकानी पड़ती है।

80 प्रतिशत से अधिक महिला जेल बन्दिनियां विचाराधीन कैदी हैं। यह विडंबना है कि महिला अपराधियों के साथ पुरुष अपराधियों के समान ही व्यवहार किया जाता है। यह जोगिन्दर कुमार (1994) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भावना के विपरीत है, जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि गिरफ्तारियां जरूरत के आधार पर होनी चाहिए। गिरफ्तारियां तभी न्याय-संगत होती हैं जब उन्हें आगे होने वाले अपराधों को रोकने, या अपराध के पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा के लिए अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया हो कि अपराधी अदालती कार्यवाही से नहीं भागेगा। महिला अपराधियों की गिरफ्तारी इस दृष्टि से तार्किक नहीं है क्योंकि उनकी आपराधिक प्रवृत्ति आमतौर पर क्षणिक होती है और आमतौर पर बदले की भावना से प्रेरित नहीं होती।

इस प्रकार, विचाराधीन महिलाओं की हिरासत न्याय प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा शक्ति का एक उद्देश्यहीन प्रदर्शन ही प्रतीत होती है। जघन्य अपराधों को छोड़कर, विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखना अनावश्यक है। कोई कारण नहीं है कि महिलाओं को अदालतों द्वारा जमानत पर रिहा न किया जा सके, भले ही उन्हें पुलिस द्वारा बिना सोचे-समझे गिरफ्तार कर लिया गया हो।

लिंग-संवेदनशील सजा-नीति के अभाव में, महिला दोषियों को भी पुरुषों के समान ही दण्डात्मक उपायों का सामना करना पड़ रहा है। निःसंदेह, महिलाएं स्वभाव से पुरुषों से भिन्न होती हैं। सामुदायिक सेवा, सजा से पहले और बाद में परिवीक्षा पर रिहाई, अनिवार्य परामर्श और जुर्माना आदि जैसे गैर-हिरासती सुधार विकल्पों की हकदार हैं। सामाजिकता पर आधारित सुधार-उपाय महिला अपराधिकता के निराकरण के लिए सबसे उपयुक्त साधन हो सकते हैं। महिलाओं को असाधारण मामलों में ही कैद किया जाना चाहिए, वह भी उनके घरों के पास की जेलों में। प्रत्येक जिला जेल में महिला अपराधियों को रखने के लिए अलग महिला बैरकों की आवश्यकता है। इन बैरकों की वास्तुकला में स्त्री-उन्मुखता और घर जैसे वातावरण की परिकल्पना होनी चाहिए।

महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों के 77 प्रतिशत पीड़ित उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या अन्य परिचित व्यक्ति होते हैं, परिणामस्वरूप, महिला कैदियों को आमतौर पर उनके प्रियजनों द्वारा त्याग दिया जाता है। अकेलापन उन्हें मानसिक अवसाद में धकेल देता है। निःसंदेह, जेल में बन्द महिलाओं का जीवन कष्ट-प्रद है, उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिदिन 16 से 18 घंटे तक भीड़भाड़ वाली बैरकों में बन्द रखा जाता है। उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैंटीन की बहुत सीमित सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। 'सैनिटरी नैपकिन' और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था असन्तोषजनक है। उन्हें काम के अवसर शायद ही उपलब्ध हों और अकेलापन उनकी नियति बन जाता है।

जेल में बन्द अधिकांश महिलाओं के पास धन का अभाव होता है, जो उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। लगभग हर महिला कैदी जेल में आते ही अपनी पहचान खोने का दंश झेलती है, वे 'अन्दर भय और बाहर भक्ति' के साथ जेलों में जीवनयापन करती हैं। प्रतिशोध और सजा का डर उन्हें बहरा और गूंगा बना देता है। महिला कैदी आमतौर पर भावनात्मक रूप से परेशान और बौद्धिक रूप से भ्रमित हो जाती हैं। फलतः शोषण का शिकार होने की स्थिति में आ जाती हैं।

पर्याप्त बाल देखभाल सुविधाओं के अभाव में महिला कैदियों के बच्चों को भी उनकी माताओं के साथ प्रतिदिन 16-18 घंटे तक बन्द रखा जाता है, जबकि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अन्तर्गत 'देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों' के रूप में उनका आदर्श निवास सरकारी बाल-गृह होने चाहिए। महिला कैदियों की समस्याएं कानून की ख़ामियों और बुनियादी ढांचे की कमियों, दोनों का परिणाम हैं। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की माताओं के लिए अनिवार्य जमानत या सज़ा के निलम्बन का प्रावधान करने के लिए कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए। महिलाओं और उनके बच्चों को उनकी वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण योजनाओं के तहत अलग लाभार्थी समूहों के रूप में वगीकृत किया जाना चाहिए।

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली अधिकांशतया पुरुष-केन्द्रित है, यह पुरुषों की, पुरुषों द्वारा, पुरुषों के लिए बनाई गई प्रतीत होती है। महिला कैदियों पर अपनी रिपोर्ट (1987) में, बन्दिनियों की दयनीय स्थिति पर टिप्पणी करते हुए, न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर ने कहा था कि सामाजिक मूल्य जड़वत हो गए हैं और सत्ता के अंग अहंकारी रूप से पुरुषोचित हैं, महिलाओं के लिए एक अलग 'भावपूर्ण दण्डशास्त्र' और 'सुधारात्मक दृष्टिकोण' अपनाने की जरूरत है। पुरुष और महिलाएं शारीरिक और भावनात्मक रूप से एक ही समूह की अलग-अलग प्रजातियां हैं, इसलिए उनके लिए अलग-अलग 'हिरासती न्याय' और पुनर्वास पैकेज की आवश्यकता है।

लेखक हरियाणा के पुलिस महानिदेशक रहे हैं।

भाषा की दीवारें ढहा रही डबिंग की क्रांति

मुकुल श्रीवास्तव

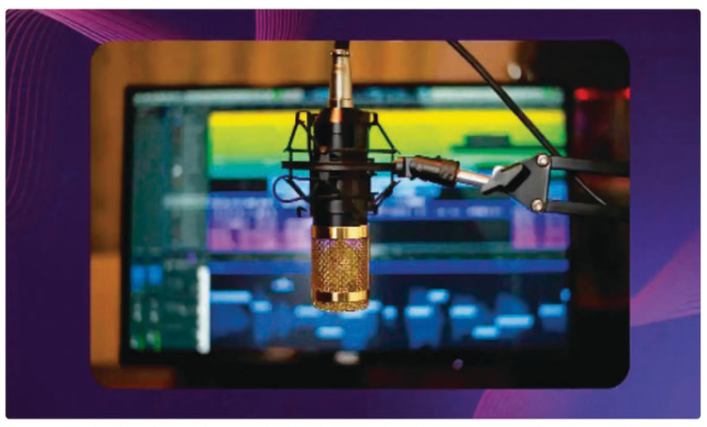

आज की डबिंग केवल भाषा परिवर्तन नहीं, बल्कि स्थानीयकरण और रचनात्मक पुनर्लेखन यानी ट्रांसक्रिएशन का माध्यम बन चुकी है। डबिंग विदेशी कंटेंट को ही भारत में लोकप्रिय नहीं बना रही, बल्कि भारतीय कंटेंट को भी दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचा रही है। भारतीय अब दूसरी भाषाओं में बने कंटेंट को भी बड़े चाव से देख रहे हैं। ओटीटी और डबिंग की इस क्रांति ने साबित कर दिया कि भाषा, सीमा और संस्कृति किसी कहानी को देखने या समझने में बाधक नहीं हैं।

एक समय था, जब डबिंग का मतलब केवल संवादों के शब्दशः अनुवाद से था, पर आज की डबिंग केवल भाषा परिवर्तन नहीं, बल्कि स्थानीयकरण और रचनात्मक पुनर्लेखन यानी ट्रांसक्रिएशन का माध्यम बन चुकी है। इस प्रक्रिया में केवल शब्द बदलना नहीं होता, बल्कि भाव-रूप में री-क्रिएशन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी अमेरिकन शो में कोई स्थानीय मुहावरा या चुटकुला है, जिसे सीधे हिंदी में समझाया नहीं जा सकता, तो उसे भारतीय संदर्भ में समतुल्य हंसी-मजाक या कहावत से बदला जाता है, ताकि संस्कृति का रंग बना रहे।

ऐसा नहीं है कि ओटीटी पर डबिंग केवल विदेशी कंटेंट को भारत में लोकप्रिय बना रही है, बल्कि यह भारतीय कंटेंट को भी दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन चुकी है। दिल्ली क्राइम को मिला इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड इस बात का प्रमाण है। वहीं आरआरआर ने विभिन्न भाषाओं में डब होकर ओटीटी के जरिये यह साबित कर दिया कि भाषा नहीं, बल्कि भावनात्मकता व कथा की ऊर्जा भारतीय सिनेमा को विश्व मंच पर पहुंचाने की असली ताकत है।

आज कोरियन ड्रामा, स्पेनिश थ्रिलर और हॉलीवुड फिल्में भारतीय घरों में उतनी ही सहजता से देखी जा रही हैं, जितना कभी हिंदी धारावाहिक देखे जाते थे। इस बदलाव के केंद्र में सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि डबिंग का वह उभरता हुआ उद्योग भी है, जिसने वैश्विक कंटेंट को स्थानीय अनुभव में बदल दिया है। अब फिल्में और वेब सीरीज एकसाथ कई भाषाओं में डब होकर रिलीज होती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कांतारा है, जिसने कन्नड़ में रिलीज होने के साथ ही हिंदी और अन्य भाषाओं में डब होकर देश भर में अपनी मजबूत पहचान बनाई। 2024 में नेटफ्लिक्स ने अपने कंटेंट को दुनिया भर में 34 से अधिक भाषाओं में डब किया, जिनमें भारतीय भाषाओं की हिस्सेदारी उल्लेखनीय रही। 2025 में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार भी क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय फिल्मों और वेब सीरीज तक, कंटेंट को हिंदी के साथ कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करा रहा है।

भारतीय युवा अब अपनी बोली-संस्कृति के साथ देश-दुनिया की अन्य संस्कृतियों, भाषाओं में बने कंटेंट को भी बड़े चाव से देख रहे हैं। ओटीटी और डबिंग की इस क्रांति ने यह साबित कर दिया है कि अब भाषा, सीमा और संस्कृति किसी कहानी को देखने या समझने में बाधक नहीं हैं। दर्शक अब वैश्विक कहानियों को अपने घर की सहजता में अनुभव कर सकते हैं और कलाकार अपनी कला की उपस्थिति दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकते हैं। आज का मनोरंजन एक वैश्विक संवाद, सांस्कृतिक पुल और रचनात्मक साझा अनुभव का प्रतीक बन चुका है। यही ओटीटी व डबिंग की असली ताकत और भविष्य की संभावनाएं हैं।

अरावली की परिभाषा में निहित हो संरक्षण का लक्ष्य

प्रो. सुखदेव सिंह

अरावली पहाड़ियों के लिए कोई एक परिभाषा अपनाने और कानून बनाने से पहले सरकार और सुप्रीम कोर्ट को सभी कोणों से इसकी जांच करनी चाहिए। ऐसी परिभाषा न हो जो इन पर्वत श्रृंखलाओं को सीधे या अप्रत्यक्ष नुकसान पहुंचा सकती है। लक्ष्य संरक्षण हो न कि बाजारी ताकतों द्वारा अंधाधुंध दोहन।

अरावली पहाड़ियां कभी अरबों साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनी ऊंचे वलित पहाड़ों की श्रृंखला थी जो लाखों साल की टूट-फूट और कटाव से घिसकर ऊंची-नीची पहाड़ियों, चोटियों व चट्टानी उभारों की श्रृंखला बन गई हैं। ये पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक हैं, कई कम ऊंची भी हैं जबकि राजस्थान के माउंट आबू पठार पर गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी समुद्र तल से 1,722 मीटर ऊंचाई तक है।

हाल ही में अरावली ने पर्यावरण विशेषज्ञों, समाज और मीडिया का ध्यान खींचा जब किसी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एमओइएफसीसी समिति द्वारा प्रस्तावित स्थानीय तल से 100 मीटर ऊंचाई वाली शर्त मंजूर करते हुए एक फैसला सुनाया जिससे सड़कों पर विरोध और बयानबाज़ी होने लगी।

2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अरावली पहाड़ों की एक समान परिभाषा बनाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत तकनीकी समिति का गठन किया गया, जिसमें समुद्र तल के बजाय स्थानीय तल आधारित राजस्थान की मौजूदा परिभाषा को शामिल किया जा सके। राजस्थान की परिभाषा पर भरोसा करते हुए, समिति ने मानदंड तैयार किए कि पहाड़ी को अरावली रेंज का हिस्सा मानने के लिए इसकी ऊंचाई आसपास के स्तर से 100 मीटर होनी चाहिए या इसे अरावली श्रृंखला में दो योग्य पहाड़ियों के बीच 500 मीटर दायरे में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर, 2025 को इस परिभाषा को मंजूर कर लिया, जिसका व्यापक विरोध हुआ।

सरकार ने इस परिभाषा का बचाव करते हुए इसे मात्र 'तकनीकी' स्पष्टीकरण बताया और कहा कि राजस्थान में यह 2006 से लागू है व इससे अरावली की हर जगह एक जैसी सुरक्षा करने में मदद मिलेगी, जबकि आलोचना के भी यही बिंदु हैं। गत 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक असंतोष का हवाला देकर 20 नवंबर के अपने आदेश पर रोक लगा दी।

अरावली के लिए टेक्निकल कमेटी द्वारा सुझाई समुद्र तल के बजाय लोकल-एरिया तल से 100 मीटर ऊंचाई वाली व्याख्या अपने आप में त्रुटिपूर्ण, अवैज्ञानिक और मनमानी आधारित है, न कि पहाड़ी की ऊंचाई मापने के यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के मुताबिक। यह क्षेत्र ऐसे भी समुद्र तल से 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है, यानी यहां के स्थानीय स्थल से 99 मीटर ऊंचा पहाड़ समुद्र तल से 199 मीटर ऊंचा होगा परन्तु टेक्निकल समिति की व्याख्या अनुसार यह पहाड़ अरावली का हिस्सा नहीं माना जायेगा जब तक 100 मीटर ऊंचे दो पहाड़ों के 500 मीटर दायरे में नहीं आएगा। इससे राजस्थान के 90 फीसदी पहाड़ अरावली रेंज से बाहर हो जाएंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण मुताबिक, राजस्थान में 12081 अरावली पहाड़ियों में से सिर्फ 1048 (8.7 फीसदी) ही 100 मीटर ऊंचाई का मापदंड पूरा करेंगी।

समुद्र तल एक यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज्ड रेफरेंस पॉइंट है, जबकि लोकल रिलीफ मनमाना है। दूसरा, राजस्थान में एक परिभाषा है और उसी के अनुसार माइनिंग की अनुमति है, जबकि दिल्ली और हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के लिए ऐसी कोई परिभाषा नहीं और माइनिंग पर रोक है। कमेटी ने राजस्थान लीगल कोड में अरावली को परिभाषित कर 'एक समानता' जोड़ी व इसे हरियाणा और अरावली रेंज साझा करने वाले सभी राज्यों में लागू किया, जिससे कानूनन हरियाणा में भी माइनिंग और अन्य गतिविधियों की अनुमति की राह खुलती है।

परिभाषा का घोषित लक्ष्य अरावली में माइनिंग को 'रेगुलेट' करना है, न कि रोकना। दिल्ली और हरियाणा में अरावली में ज़्यादा अलग-थलग छोटी पहाड़ियां और चोटियां हैं। यही वह मुख्य बात है जिस पर रियल एस्टेट कारोबारियों की नज़र है, जो गुड़गांव व फरीदाबाद जिलों में अपने कार्य को कानूनी रूप देना चाहते हैं, जहां वे किसी न किसी तरह से पहले ही काम कर रहे हैं, जिससे वहां जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। साल 2023 के एक सर्वे में, इस इलाके में 786 एकड़ ज़मीन पर मंज़ूरशुदा इमारतों के अलावा, लग्ज़री फार्म हाउस, रिसॉर्ट, बैंक्वेट हॉल, घर, धार्मिक स्थल और शैक्षणिक संस्थान वगैरह के रूप में 6793 गैर-कानूनी स्ट्रक्चर पाए गए।

यह बाज़ार-संचालित खनन, वनों की कटाई और रियल एस्टेट विकास है जिससे अरावली पहाड़ियों को खतरा है। एक बार जब अरावली के कुछ हिस्सों को उसके दायरे से बाहर रखने के लिए परिभाषित किया जाएगा, तो खनन और रियल एस्टेट कंपनियों को न उस क्षेत्र पर कानूनन कब्ज़ा करने की अनुमति मिल जाएगी; इसके बाद उन्हें अरावली के दिल में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकेगा। बाज़ार-संचालित ताकतें इसी तरह काम करती हैं। 'मुनाफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा करने' के मकसद से काम करने वाली बाज़ार-संचालित ताकतें मानवीय, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और प्राकृतिक चिंताओं के 'बाहरी प्रभावों' पर ध्यान नहीं देतीं, जिसके चलते प्रदूषण, संसाधनों की कमी और सांस्कृतिक विरासत का नुकसान होता है।

यहीं पर सरकारों को हस्तक्षेप करना होगा और बाज़ार की ताकतों को अपने पक्ष में सब कुछ तय करने देने के बजाय मानव कल्याण, पर्यावरण और पारिस्थितिक संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। इसलिए, अरावली पहाड़ियों के लिए एक ऐसी परिभाषा, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक को सीधे या अप्रत्यक्ष नुकसान पहुंचा सकती है, अपनाने और कानून बनाने से पहले सरकार और सुप्रीम कोर्ट को सभी कोणों से इसकी जांच करनी चाहिए।

ममता की छाँव

ममता की छाँव तले, सुखद जीवन पले,
आसमाँ उड़ान भरें,
बेटियाँ संसार में।

मा त-पिता आशीष से,
कर्तव्य पालन करें,
समर्पण भाव सदा,
रखते सत्कार में।

म न में उमंग लिए, जीत का संकल्प लिए,
आगे-आगे बढ़ रही,
कार्य के विस्तार में।

मा तृत्व सँजोती माएँ,
साहस के बीज बोती,
संस्कार सिखातीं सदा,
सुषमा दुलार में।

-: सुषमा प्रेम पटेल , रायपुर :-

सुविचार

कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544
www.onlytds.com

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

यादव महासभा का युवक-युवती परिचय सम्मेलन 11 को

दुर्ग। नगर यादव महासभा द्वारा 11 जनवरी को दोपहर एक बजे से यादव छात्रावास पचरीपारा वार्ड नंबर-28 दुर्ग में यादव मिलन समारोह एवं युवक युवती सम्मेलन एवं गीता जयंती का कार्यक्रम रखा गया है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि केबिनेट मंत्री गजेंन्द्र यादव होंगे जबकि अध्यक्षता सांसद विजय बघेल करेंगे। विशेष के रूप में विधायक ललित चंद्राकर, महापौर अल्का बाधमार, दीपक ताराचंद साहू, शिवराज राउत, राजेश ताम्रकार, अजय यादव एवं पार्षद ममता ओमप्रकाश पार्षद, बबीता यादव उपस्थित रहेंगे।

विभागीय परीक्षा का आयोजन 27 जनवरी से बीआईटी दुर्ग में

दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन गृह-सी विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) के अंतर्गत शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन 27 जनवरी से 03 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया है। आयुक्त दुर्ग संभाग द्वारा विभागीय परीक्षा संचालन हेतु भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी) दुर्ग को परीक्षा केन्द्र नामांकित किया गया है।

महापौर बाघमार ने किया वाल्व बदलने के कार्य का निरीक्षण

दुर्ग। नगर पालिक निगम द्वारा मालवीय नगर कॉम्प्लेक्स के पास 24 एमएलडी फिल्टर प्लांट से जुड़े 600 एम.एम.के 2 बटर फ्लाई वाल्व को बदला जा रहा है। महापौर अलका बाघमार, प्रभारी लीना दिनेश देवांगन के साथ स्वयं पहुंची तथा जल आपूर्ति पर इसके प्रभाव की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि मरम्मत कार्य में किसी भी प्रकार की देरी न हो और रात भर कार्य जारी रखे ताकि लम्बे समय तक नागरिकों को पानी की परेशानी का सामना न करना पड़े।

सफाई की हकीकत देखने महापौर पहुंचीं पटरी पार

दुर्ग। नगर निगम महापौर अलका बाघमार ने आज सुबह आयुक्त सुमित अग्रवाल एवं एमआईसी देव नारायण चंद्राकर, ज्ञानेश्वर ताम्रकर, वार्ड पार्षद रंजीता पाटिल, मंडल अध्यक्ष मनमोहन शर्मा और उपअभियन्ता पंकज साहू, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, कर्मशाला अधीक्षक शोएब अहमद, अतिक्रमण विभाग चंदन शर्मा सहित अमला की टीम के साथ शहर के पटरी पार वार्ड क्रमांक 19 तितुरडीह क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति देखी और आवश्यक निर्देश दिए।

बीएसपी बार एंड रॉड मिल की तीनों टीमों को एनसीक्यूसी में 'पार एक्सीलेंस' अवार्ड

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के बार एवं रॉड मिल (बीआरएम) विभाग की तीन टीमों—आरोहण, उन्नयन एवं सारथी ने दिसंबर 2025 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित नेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी सर्कल्स (एनसीक्यूसी-2025) में देशभर से भाग लेने वाली टीमों के बीच टीम उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित 'पार एक्सीलेंस अवार्ड' अर्जित किया। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में तीनों टीमों की उपलब्धियों ने भिलाई इस्पात संयंत्र को गौरवान्वित किया है।

टीम आरोहण ने इंटीग्रेटेड सेफ्टी सर्कल श्रेणी में प्रभावशाली प्रस्तुति देकर पार एक्सीलेंस अवार्ड अपने नाम किया। टीम आरोहण का मार्गदर्शन उप महाप्रबंधक विजी मथाई ने किया। टीम में अपु बेहेरा (टीम लीडर), एन सतीश कुमार (डिप्टी लीडर) तथा मनोज कुमार, चंदन सिंह एवं एम श्रीनू सदस्य के रूप में शामिल रहे।

टीम उन्नयन ने लीन क्वालिटी सर्कल श्रेणी में पार एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त किया। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ प्रबंधक राजुल पाण्डेय ने किया, जबकि एन. सतीष कुमार (टीम लीडर) एवं अपु बेहेरा (डिप्टी लीडर) सदस्य रहे।

वहीं टीम सारथी ने क्वालिटी सर्कल श्रेणी में पार एक्सीलेंस अवार्ड हासिल किया। टीम का मार्गदर्शन उप प्रबंधक श्री अनिल कुमार द्विवेदी ने किया। टीम में दीपेश कुमार चुघ (टीम लीडर), धनराज साहू (डिप्टी लीडर) तथा शुभम शिंदे, कुंते लाल एवं यशवंत कुमार शामिल रहे।

मिल के विभागाध्यक्ष एवं मुख्य महाप्रबंधक योगेश शास्त्री ने इस उपलब्धि पर सभी टीमों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना बीआरएम की सुदृढ़ कार्यसंस्कृति को दर्शाता है।

सेल ने दिसम्बर में सर्वकालिक सर्वाधिक बिक्री का बनाया रिकार्ड, ग्रोथ रेट बरकरार

इसी अवधि में 2024 के मुकाबले 2025 में 37 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई/नई दिल्ली। देश की महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और देश के अग्रणी इस्पात उत्पादकों में से एक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिसंबर 2025 के दौरान 2.1 मिलियन टन (अनंतिम) की विक्रय दर्ज करके एक और उपलब्धि हासिल की है। यह दिसंबर 2024 में हासिल की गई 1.5 मिलियन टन की बिक्री की तुलना में लगभग 37 प्रतिशत की भारी वृद्धि है।

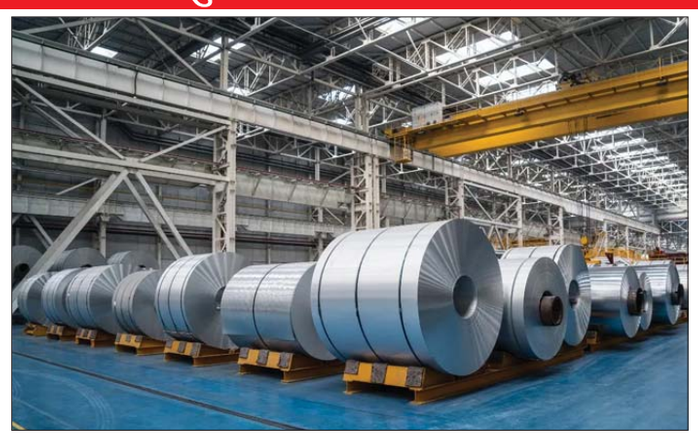

यह दिसंबर महीने के लिए कंपनी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस दौरान कंपनी ने विभिन्न उत्पाद श्रेणियों और बिक्रय माध्यमों में नए कीर्तिमान स्थापित किए, साथ ही इन्वेंट्री में भी महत्वपूर्ण कमी आई है। यह प्रदर्शन सेल द्वारा ग्राहकों को समय पर डिलीवरी देने पर फोकस करने की वजह से रहा। हाल के दिनों में नए उत्साह के साथ ब्रांडिंग पहलों पर भी जोर दे रहा है।

दिसंबर महीने के दौरान इस शानदार प्रदर्शन ने सेल को वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपनी विकास गति को बनाए रखने में मदद की है। अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान कुल बिक्री मात्रा 14.7 मिलियन टन (अनंतिम) तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की 12.6 मिलियन टन की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि है। घरेलू बाजार में बनाए गए रिकॉर्ड के अतिरिक्त, निर्यात मात्रा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वैश्विक स्तर पर सेल की बढ़ती उपस्थिति को रेखांकित करती है।

यह निरंतर सुधार, सेल की मजबूत बाजार उपस्थिति, ग्राहक-केंद्रित पहलों और परिचालन उत्कृष्टता को उजागर करता है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में, सेल की यह रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां कंपनी की न केवल भारत के अग्रणी इस्पात निर्माताओं में इसकी स्थिति मजबूत करती हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी शीर्ष इस्पात कंपनियों के बीच भी, सेल को एक उच्च पायदान पर ले जाने की उम्मीद दिलाती है।

ऑनलाइन टूर एडवांस एवं बिल आवेदन प्रणाली का शुभारंभ

भिलाई इस्पात संयंत्र के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सी एंड आईटी विभाग द्वारा ऑनलाइन टूर एडवांस एवं बिल आवेदन प्रणाली का सफलतापूर्वक विनिर्माण किया गया है। इस नवीन डिजिटल प्रणाली का उद्घाटन दिनांक 05 जनवरी 2026 को कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) श्री प्रवीण निगम एवं कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार द्वारा किया गया। कार्यपालक निदेशकगण ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे कर्मचारी-हितैषी, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली न केवल कार्य प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी, बल्कि कर्मचारियों के समय एवं संसाधनों की भी बचत सुनिश्चित करेगी।

मुड़पार से हैवी क्रैशर मशीन को हटाए जाने दिया आवेदन

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में जनसामान्य से मुलाकात कर उनकी समस्याएं को सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण के निर्देश दिए। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 100 आवेदन प्राप्त हुए।

ग्राम पंचायत मुड़पार के सरपंच व ग्रामवासियों ने बताया कि जिले के ग्राम पंचायत मुड़पार में नव स्थापित हैवी क्रैशर मशीन से उत्पन्न धूल व शोर के कारण ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मशीन की स्थापना ग्राम पंचायत मुड़पार के आबादी क्षेत्र में होने के कारण ग्रामवासी आक्रोशित है। उन्होंने क्रैशर मशीन को आबादी क्षेत्र से दूर स्थानांतरित करने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने खनिज विभाग को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

अहिवारा वार्डवासियों ने बताया कि अहिवारा बस स्टैंड क्षेत्र में मुख्य सड़क पर अवैध रूप से फ्ल विक्रेताओं व अन्य दुकानों के लगने से जनसमस्या गंभीर होती जा रही है।

महिलाओं, बुजुर्गों, स्कूली बच्चों और यात्रियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम लग रहा है, वहीं स्थायी दुकानदारों का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है।

स्थानीय लोगों ने अवैध अतिक्रमण हटाकर ठेले एवं दुकानों के लिए व्यवस्थित स्थान निर्धारित करने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी अहिवारा को निरीक्षण कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। ग्राम उमरपोटी में शासकीय भूमि पर बिना चिमनी संचालित ईंट भट्टी ग्रामीणों के लिए गंभीर परेशानी बन गई है। ग्रामवासियों ने बताया कि पिछले 10-12 वर्षों से ईंट भट्टी का संचालन किया जा रहा है, जिससे आसपास के आवासीय क्षेत्र और कृषि भूमि में धुआं व डस्ट फैल रही है। प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और धान-गेहूं की फसल भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने ईंट भट्टी को तत्काल बंद कराने की मांग की है। भेड़सर स्थित ठेठवार तालाब के डूबान क्षेत्र और तालाब पार पर अवैध कब्जे की भी शिकायत मिली।

बकाया किराया नहीं चुकाने पर आकाशगंगा की 9 दुकानें सील

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। भिलाई नगर निगम ने बकाया किराया वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए आकाशगंगा बिजनेस कॉम्प्लेक्स में संचालित 9 दुकानों को सील कर दिया। निगम से मिली जानकारी के अनुसार, उक्त कॉम्प्लेक्स की दुकानें लीज पर आवंटित की गई थीं, लेकिन संबंधित दुकानदारों द्वारा लंबे समय से निर्धारित किराया जमा नहीं किया जा रहा था। इन दुकानों पर 1 लाख से लेकर 8 लाख रुपये तक का किराया बकाया बताया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और निगम अधिकारियों के बीच काफी देर तक बहस भी हुई, लेकिन जब निगम की ओर से पूर्व में जारी नोटिस प्रस्तुत किए गए तो दुकानदार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद निगम ने नियमानुसार दुकानों को सील करने की कार्रवाई की। निगम अधिकारियों का कहना है कि कुछ दुकानदारों ने मौके पर किराया जमा करने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन जब तक पूरी बकाया राशि अदा नहीं की जाती, तब तक सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बकाया किराया नहीं चुकाने वालों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से व्यावसायिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

पारीवारिक विवाद में समझौता हो प्राथमिक विकल्प

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग ने वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों में मध्यस्थता को प्राथमिक विकल्प के रूप में अपनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट के प्रकरणों में संवाद, समझौता एवं आपसी सहमति के माध्यम से समाधान न केवल समय और व्यय की बचत करता है, बल्कि पारिवारिक संबंधों को भी सुरक्षित रखने में सहायक होता है।

बैठक के दौरान फैमिली कोर्ट में लंबित एवं सुलह योग्य मामलों की पहचान, प्री-लिटिगेशन स्तर पर मध्यस्थता एवं काउंसलिंग को प्रोत्साहित करने, पक्षकारों को मध्यस्थता के लाभों से अवगत कराने तथा मामलों के त्वरित संदर्भन हेतु प्रभावी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। काउंसलर्स द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए तथा व्यवहारिक सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।

'मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0' अभियान को प्रभावी एवं सफल बनाने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा फैमिली कोर्ट के न्यायाधीशगण तथा काउंसलर्स के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई थी।

बैठक का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण, त्वरित एवं स्थायी समाधान हेतु मध्यस्थता एवं काउंसलिंग की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाना रहा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने न्यायाधीशगण एवं काउंसलर्स को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए ''मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0'' अभियान के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर साकार करें, ताकि अधिक से अधिक पारिवारिक विवादों का समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जा सके। बैठक के पश्चात् फैमिली कोर्ट में मध्यस्थता एवं काउंसलिंग के माध्यम से मामलों के निराकरण की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ किए जाने पर सहमति बनी, जिससे अभियान को व्यापक सफलता मिलने की अपेक्षा व्यक्त की गई।

मानवाधिकार आयोग की आयुक्त से सौजन्य भेंट

भिलाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग की टीम ने भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय से सौजन्य मुलाकात की। आयोग के पदाधिकारियों ने आयुक्त महोदय को उनके दायित्वों के लिए बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

इस दौरान आयोग के जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार झलरिया, प्रदेश सचिव नागेंद्र सूर्यवंशी जी एवं जिला उपाध्यक्ष गोल्डी रोनाल्डो जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार के क्षेत्र में सकारात्मक कार्यों पर चर्चा की गई। आयुक्त श्री पाण्डेय ने आयोग की टीम का आभार व्यक्त करते हुए सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर निरंतर संवाद और समन्वय बनाए रखने की बात कही।

आईआईटी भिलाई में ई-प्रेक 2026 का समापन

शोध का अनुप्रयोग-उन्मुख होना जरूरी - विज्ञानश्री

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई में तीन दिनों तक चले ज्ञान और तकनीक के महाकुंभ, '6वें आईआईटी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (ई-प्रेक 2026)', का भव्य समापन हुआ। विद्युत अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश-विदेश के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने इलेक्ट्रिक पावर और नवीकरणीय ऊर्जा के भविष्य पर मंथन किया।

2 से 4 जनवरी तक चले इस कार्यक्रम ने न केवल अनुसंधान की नई दिशाएं तय कीं, बल्कि वैश्विक शैक्षणिक सहयोग को भी एक मजबूत मंच प्रदान किया।

समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर और 'विज्ञानश्री' पुरस्कार विजेता, प्रो. भीम सिंह ने शोध की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में केवल शोध करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे 'अनुप्रयोग-उन्मुख' बनाना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि नवाचार और स्टार्टअप आधारित समाधान ही भविष्य में रोजगार सृजन का मुख्य आधार बनेंगे, जिससे देश तकनीकी रूप से और अधिक आत्मनिर्भर होगा।

इस गरिमामयी अवसर पर आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। डीन (अनुसंधान एवं विकास) डॉ. संतोष बिस्वास और विद्युत अभियांत्रिकी विभागाध्यक्ष डॉ. अविशेक अधिकारी ने भी अपने विचार साझा किए।

शिक्षा जगत और उद्योग जगत के दिग्गजों द्वारा दिए गए मुख्य भाषणों ने प्रतिभागियों को बिजली क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों और आधुनिक समाधानों से अवगत कराया।

सम्मेलन में 500 से अधिक शोधपत्र प्राप्त हुए थे। 235 उच्च गुणवत्ता वाले शोधपत्रों को ही प्रस्तुति के लिए चुना गया।

हाउसिंग बोर्ड के सी-ब्लॉक के खिलाफ ग्रामीण बैठे धरने पर

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। दुर्ग के रिसाली निगम वार्ड 3 में हाउसिंग बोर्ड के सी-ब्लॉक के निर्माण को लेकर वार्डवासियों ने दो दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यह वार्ड का इकलौता खेल मैदान है और नए कॉलोनी के निर्माण से लगभग 70 घरों को तोड़ना पड़ेगा।

हाउसिंग बोर्ड ने मैदान के चारों ओर बाउंड्री वॉल लगाकर निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसे देखते हुए, स्थानीय लोग विरोध स्वरूप धरने पर बैठे हैं।

वार्ड की पार्षद सारिका साहू ने बताया कि इस खेल मैदान को बचाने के लिए 'खेल मैदान बचाओ संघर्ष समिति' बनाई गई थी और कलेक्टर सहित विधायक तक आवेदन भेजे गए थे। हालांकि, अब तक किसी प्रशासनिक कार्रवाई की उम्मीद पूरी नहीं हुई।

धरने का समर्थन करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा ने कहा कि निगम कुछ लोगों को नोटिस देकर जमीन खाली करने को कह रहा है। लेकिन यदि लोग संगठित रहेंगे, तो उनका विरोध सफल हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वे कलेक्टर और बीएसपी प्रबंधन से बातचीत करेंगे, ताकि खेल मैदान संरक्षित रखा जा सके।

स्थानीय लोग अब और अधिक सक्रिय हो गए हैं और हाउसिंग बोर्ड के निर्माण कार्य पर लगातार नजर रख रहे हैं। प्रशासन और नागरिकों के बीच यह विवाद फिलहाल जारी है।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
Washing Machine / Cooler
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 22
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line

खास खबर

मुख्यमंत्री निवास रायपुर में 8 को होगा जनदर्शन

रायपुर। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में 08 जनवरी गुरुवार को जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके।

मां सर्वमंगला मंदिर घाट पर भव्य हसदेव आरती

कोरबा। नमामि हसदेव सेवा समिति हसदेव नदी और इसके सहायक नदियों के प्रदूषण को कम करने, संरक्षण करने और तट के सौंदर्यीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार को मां सर्वमंगला मंदिर घाट के समीप किया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान भोजराम देवांगन अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ और विशिष्ट यजमान नरेन्द्र कुमार अग्रवाल महामंत्री, चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कोरबा सहित अन्य उपस्थित थे।

माचकोट रेंज में बाघ की मौजूदगी पर हाई अलर्ट जारी

जगदलपुर। कांगेर घाटी, जगदलपुर रेंज एवं माचकोट रेंज में बाघ की मौजूदगी सामने आई है। टाइगर मूवमेंट की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद वन विभाग हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। इन सभी क्षेत्रों को अलर्ट जोन घोषित करते हुए सघन निरीक्षण और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। वन अमले को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों और पर्यटकों से अपील की है कि वे जंगल क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचें, सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दें।

प्रदेश साहू संघ कल करेगा राजिम महोत्सव का आयोजन

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ राजिम जयंती महोत्सव का आयोजन 7 जनवरी को राजिम में करेगा। इस अवसर पर श्रद्धालु हजारों की संख्या में भक्तिन राजिम माता के दर्शन कर कार्यक्रम में शामिल होंगे। उक्त जानकारी संघ के अध्यक्ष डॉ. नीरेन्द्र साहू ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, उपमुख्यमंत्री अरूण साव, तोखन साहू, केन्द्रीय राज्यमंत्री भारत शासन एवं चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा होंगे।

वूमन फॉर ट्री' के तहत जिला कार्यालय परिसर में पौधरोपण

कोण्डागांव। नगर प्रशासन की मिशन अमृत के अभियान 'वूमन फॉर ट्री' के तहत पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को लेकर जिला कार्यालय परिसर में पौधा रोपण किया गया। इस मौके पर बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक लता उसेण्डी, कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना, जिला पंचायत अध्यक्ष रीता शोरी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने पौधरोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष टोमेंद्र ठाकुर, सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिली प्रोत्साहन राशि

बीजापुर। कलेक्टर संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नीति के अंतर्गत जिले के 92 प्रशिक्षणरत आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये प्रतिमाह की दर से राशि प्रदान किए जाने हेतु 9.2 लाख के आहरण एवं संवितरण की स्वीकृति दी गई है।

मरार पटेल समाज के प्रत्येक व्यक्ति में है सहकारिता की भावना : उपमुख्यमंत्री

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। माता शाकम्बरी जयंती के अवसर पर सोमवार को उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा रायपुर के घड़ी चौक में आयोजित जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने माता शाकम्बरी की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की और पटेल समाज के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर उन्होंने लोगों को सब्जियों का निःशुल्क वितरण भी किया।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने समाजजनों को संबोधित करते हुए कहा कि मरार पटेल समाज एक उद्यमी, संगठित और सुव्यवस्थित समाज है। अपने श्रम और उद्यम के आधार पर उनकी अलग पहचान बनाई है।

उन्होंने बताया कि समाज के श्रम को बाड़ी में उत्पादन से लेकर देश के बड़े बड़े बाजारों तक उनके उत्पादों को पहुंचा कर उचित प्रतिफल दिलाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह द्वारा शाकम्बरी बोर्ड का गठन किया गया था। जिसका बहुत अच्छा

परिणाम हमें प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि मरार पटेल समाज में सहकारिता की भावना हर व्यक्ति में विद्यमान है। जन जन और हर मन में स्वाभाविकता से बसे इस सहकारिता के भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है और समाज एवं प्रदेश के विकास के लिए कार्य करना है।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने माता शाकम्बरी से प्रार्थना करते हुए कहा कि माता की कृपा से सभी के घरों में धन-धान्य की वर्षा हो, खेत-खलिहान लहलहाते रहें, सभी नागरिक स्वस्थ और सुखी रहें तथा राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर गांव, गरीब, किसान और श्रमिक के उत्थान के लिए सतत प्रयास कर रही है।

इस अवसर पर राज्य मरार पटेल समाज के अध्यक्ष शंकर पटेल, राम कुमार पटेल, अशोक पटेल, परदेशी पटेल, केके पाटिल, ब्रम्हदेव पटेल, राजेन्द्र पटेल, मोतीराम पटेल, प्रमोद पटेल, बाकीराम पटेल, ईश्वर पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं समाज के सदस्य उपस्थित रहे।

कवर्धा प्रीमियर लीग से क्रिकेटर्स को मिला मंच, प्रतिभा निखारने का मौका

- **अंतिम गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में वार्ड नंबर 8 ने जीता खिताब**

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल पर आयोजित कवर्धा प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला कवर्धा के वार्ड नंबर 08 एवं ग्राम सारी के मध्य कवर्धा के करपात्री स्टेडियम में खेला गया। यह मुकाबला दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रहा, जिसमें अंतिम गेंद पर खेल का परिणाम तय हुआ।

फाइनल मैच में वार्ड नंबर 08 की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्राम सारी को 101 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए ग्राम सारी की टीम को वार्ड नंबर 08 के गेंदबाजों ने अपने शानदार गेंदबाजी और अनुशासित खेल द्वारा परास्त कर टीम विजेता बनी और वार्ड नंबर 08 ने कवर्धा प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया।

इस अवसर पर तीसरे स्थान के लिए ग्राम बरेंडा एवं कवर्धा के वार्ड नंबर 09 के मध्य मुकाबला खेला गया, जिसमें ग्राम बरेंडा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज कर तीसरे स्थान प्राप्त किया।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने फाइनल मुकाबले से पूर्व विधिवत पूजा-अर्चना कर मैच का शुभारंभ किया। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और खेल भावना के साथ खेलने का संदेश दिया। मैच के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने भी क्रिकेट में हाथ आजमाया और नगर पालिका अध्यक्ष एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष की गेंदों पर आकर्षक लंबे शॉट लगाया, जिससे मैदान में मौजूद खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ग्राम बरेंडा में मिनी स्टेडियम निर्माण की घोषणा भी की।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी प्रतिभाओं को बेहतर मंच और सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, ताकि युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। उन्होंने कवर्धा प्रीमियर लीग में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों, आयोजकों एवं खेल प्रेमियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस आयोजन ने जिले में खेल संस्कृति को नई दिशा दी है। उन्होंने खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासन, समर्पण और खेल भावना की विशेष रूप से सराहना की। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक दिशा, मंच और प्रोत्साहन प्रदान किया जाता रहेगा, ताकि कवर्धा जिले से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उभर सकें।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा प्रीमियर लीग के समापन अवसर पर विजेता एवं उपविजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कवर्धा वार्ड नंबर 08 की टीम को 1 लाख 11 हजार रुपए की पुरस्कार राशि एवं आकर्षक शील्ड प्रदान की गई। वहीं, प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान हासिल करने वाली ग्राम सारी की टीम को 51 हजार रुपए एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली ग्राम बरेंडा की टीम को 31 हजार रुपए की पुरस्कार राशि एवं शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया।

उन्होंने बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफद सीरिज खिलाड़ियों को भी शील्ड मोमेंटो देकर सम्मानित किया। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने सभी विजेता एवं सहभागी टीमों को बधाई देते हुए कहा कि कवर्धा प्रीमियर लीग जैसे आयोजनों से जिले में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला है तथा युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का सशक्त मंच प्राप्त हो रहा है।

तुअर, उड़द, मूंग, सोयबीन के लिए समर्थन मूल्य की मंजूरी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान छत्तीसगढ़ में दाल एवं तिलहनी फसलों की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना लागू करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

केंद्रीय मंत्री द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में निम्नानुसार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 21 हजार 330 मीट्रिक टन तुअर, 25 हजार 530 मीट्रिक टन उड़द, 240 मीट्रिक टन मूंग, 4 हजार 210 मीट्रिक टन सोयाबीन और 4 हजार 210 मीट्रिक टन मूंगफली खरीद की मंजूरी दी गई है।

इन फसलों की खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित दाम प्राप्त होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में आशा व्यक्त की है कि इस निर्णय से तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी तथा उन्हें औने-पौने दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एमएसपी पर खरीद की सभी तैयारियाँ समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करेगी। इस निर्णय से राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, दलहन एवं तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।

कोण्डागांव की विधायक उसेण्डी ने मोर सुआद दीदी की रसोई का किया शुभारंभ

श्रीकंचनपथ समाचार

कोण्डागांव। बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक लता उसेण्डी ने गुरुवार शाम कोण्डागांव में दीदी की रसोई पहल के अंतर्गत 'मोर सुआद' का शुभारंभ किया।

इस दौरान कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना भी उपस्थित रहे। शुभारंभ अवसर पर विधायक उसेण्डी ने कहा कि घर, परिवार की जिम्मेदारियों के साथ बाहर निकलकर कार्य करना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हमारी बहनें इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लखपति दीदी पहल सहित एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने दीदी की रसोई की सराहना करते हुए कहा कि यहां लोगों को पारंपरिक संस्कृति की झलक के साथ घर जैसा स्वाद मिलेगा।

इस अवसर पर कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना ने नवाचार के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि भविष्य में यहां सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा, जिससे यहां आने वाले लागों को बेहतर वातावरण के साथ-साथ घर के स्वाद का अनुभव प्राप्त हो सके।

पार्षद सोनामणि, दीपेश अरोरा, गोपाल दीक्षित सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई के मार्गदर्शन में एनआरएलएम के जिला मिशन प्रबंधक विनय सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक कुंजलाल सिन्हा, दुर्योधन मेंघ सहित एनआरएलएम की टीम का मोर सुआद के शुभारंभ में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

महतारी वंदन योजना से गृहिणियों को मिली जुबान : लक्ष्मी

परिवार में बढ़ी भूमिका, 69 लाख महिलाओं को मिले 14 हजार करोड़

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विगत दो वर्षों में छत्तीसगढ़ शासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक और ठोस बदलाव लाने के लिए ऐतिहासिक पहल की है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सम्मान, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से 69 लाख से अधिक महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिला है और अब तक 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है। योजना का सामाजिक प्रभाव यह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं अब पारिवारिक और आर्थिक निर्णयों में स्वतंत्र भूमिका निभा रही हैं। वहीं

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 4.81 लाख महिलाओं को 237 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है, जिससे छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

प्रेस वार्ता में मंत्री ने कहा कि राज्य में कुपोषण के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2025 तक स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। 19 लाख से अधिक हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें महिला स्व सहायता समूहों की भागीदारी से पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण वितरण सुनिश्चित हुआ है।

महिला सुरक्षा एवं संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से हजारों महिलाओं और बच्चों को त्वरित सहायता प्रदान की गई है। बाल संरक्षण सेवाओं, दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर और न्यायिक प्रकरणों के निराकरण में भी छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन, नई नियुक्तियों, डिजिटल उपस्थिति प्रणाली और ई-भर्ती पोर्टल जैसी पहलों से विभागीय कार्यप्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हजारों बेटियों के विवाह गरिमामय ढंग से संपन्न कराए गए हैं।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं छत्तीसगढ़ को एक सुरक्षित, सशक्त और समावेशी राज्य बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं।

खनन प्रभावित बच्चों को मिला सहारा, 297 बच्चे हुए सुपोषित

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। खनन प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत अंतिम व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की राज्य शासन की प्रतिबद्धता को रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में साकार रूप मिलता दिखाई दे रहा है। जिला खनिज संस्थान न्यास निधि (डीएमएफ) रायगढ़ के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में की गई योजनाबद्ध पहल ने कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहे बच्चों के जीवन में नई उम्मीद जगाई है।

इसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तमनार में 10 बिस्तरीय पोषण पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी) भवन का निर्माण डीएमएफ मद से निर्माण कर कुपोषण से मुक्त बनाने के लिए क्षेत्र को सौगात दी गई। इस भवन में आज पोषण पुनर्वास केंद्र के रूप में संचालित हो रही है और क्षेत्र के कुपोषित बच्चों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है।

वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तमनार में संचालित एनआरसी के माध्यम से विकासखण्ड तमनार एवं विकासखण्ड घरघोड़ा के कुल 297 कुपोषित बच्चों को लाभ मिला। इन बच्चों को 15 दिवस के लिए एनआरसी में भर्ती कर चिकित्सकीय देखरेख के साथ-साथ प्रोटीन युक्त, संतुलित एवं पौष्टिक आहार प्रदान किया गया, जिससे उनके शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास को भी मजबूती मिली।

एनआरसी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहां बच्चों के साथ उनकी माताओं को भी देखरेख की प्रक्रिया में सहभागी बनाया जाता है। बच्चों की समुचित देखभाल के एवज में माताओं को प्रोत्साहन राशि भी प्रदाय की गई, जिससे परिवार की सहभागिता बढ़ी और उपचार की प्रभावशीलता सुनिश्चित हुई। इसका सकारात्मक असर यह रहा कि भर्ती अवधि के दौरान बच्चों के वजन, ऊर्जा स्तर और समग्र स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया।

गौरतलब है कि रायगढ़ जिले का तमनार क्षेत्र खनन प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। ऐसे क्षेत्रों में डीएमएफ मद से बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य शासन द्वारा योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। पोषण पुनर्वास केन्द्र इसका जीवंत उदाहरण बन कर उभर रहा है, जहां खनन से प्रभावित समुदायों के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। डीएमएफ योजना के तहत स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में किए जा रहे ये प्रयास 'अंत्योदय' की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं।

पीएम- ई विद्या डीटीएच चैनल के माध्यम से शैक्षिक प्रसारण कार्यक्रम

बलौदाबाजार। पीएम- ई विद्या योजना के तहत राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार राज्य में कक्षा 9 से 12वीं के समस्त विषयों की सामाग्रियों के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण डीटीएच चैनल सहित अन्य टेलीविजन चैनलों में किया जा रहा है।

कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए माह जनवरी 2026 का मासिक कैलेंडर का क्लिकेबल पीडीएफ पोस्टर तैयार है। जिसमें किसी भी तिथि को टच करने से उस तिथि में प्रसारित होने समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों की सारणी कक्षावार और विषयवार खुल जाता है। इससे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को प्रसारण की सही जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जनवरी 2026 के लिए मासिक कैलेंडर का क्लिकेबल पीडीएफ पोस्टर जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे द्वारा जारी सभी विद्यालयों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थी कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाने आह्वान किया गया है।

जन्मदिन पर दीपिका पादुकोण ने शुरू की एक नई पहल, नए टैलेंट को देंगी पहचान, युवाओं को मिलेगा बड़ा मौका

बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर सेलेब्स से लेकर फैंस तक उन्हें बधाई दे रहे हैं। अब दीपिका ने भी जन्मदिन के मौके पर अपने फैंस को एक रिटर्न गिफ्ट दिया है। उन्होंने नई क्रिएटिव जेनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। जानिए क्या है ये प्रोग्राम

दीपिका पादुकोण ने अपने जन्मदिन पर नए और युवा क्रिएटिव टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की है। सच्ची कहानियों और नए टैलेंट को आगे बढ़ाने की सोच के साथ दीपिका ने 'द ऑनसेट प्रोग्राम' की शुरुआत की घोषणा की है। यह उनके क्रिएट विद मी प्लेटफॉर्म का अगला कदम है। इसका मकसद ऐसे नए क्रिएटिव आर्टिस्ट्स को मौका देना है, जो इंडियन फिल्म, टीवी और विज्ञापन की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके टैलेंट सही मायनों में सामने आ सके इसलिए यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके पहले राउंड में लिखना, निर्देशन, कैमरा, लाइट, एडिटिंग, साउंड, आर्ट, कपड़ों की डिज़ाइन, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप और प्रोडक्शन जैसे काम शामिल होंगे।

दीपिका ने जताई खुशी

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए दीपिका ने कहा, 'पिछले एक साल से मैं देश और उसके बाहर से बेहतरीन क्रिएटिव टैलेंट को पहचानने और उन्हें देखने, सुनने का मंच देने के लिए गंभीरता से सोच रही हूं। द ऑनसेट प्रोग्राम के लॉन्च का एलान करते हुए मैं बेहद खुश हूं और अगली पीढ़ी के क्रिएटिव टैलेंट से आप सभी को मिलवाने का मुझे बेसब्री से इंतजार है।' द ऑनसेट प्रोग्राम onsetprogram.in पर देखा जा सकता है। यहां लोग अपना काम भेज सकते हैं और इंडस्ट्री के बेहतरीन लोगों के साथ काम करने का मौका पा सकते हैं।

शाहरुख के साथ 'किंग' में नजर आएंगी दीपिका

वर्कफ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण आखिरी बार 'सिंघम अगेन' में नजर आई थीं। यह दीवाली 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके बाद से दीपिका 2025 में अपनी आठ घंटे काम की शिफ्ट को लेकर सुर्खियों में रहीं। लेकिन बड़े पर्दे से वो पूरे साल ही दूर रहीं। अब दीपिका शाहरुख खान के साथ 'किंग' और अल्लू अर्जुन के साथ एटली द्वारा बनाई जा रही एक बड़ी फिल्म में नजर आएंगी। हालांकि, अभी तक इसका टाइटल सामने नहीं आया है।

आगे बढ़ते रहो आप, पति रणबीर और बेटी राहा के साथ समंदर किनारे मस्ती करती नजर आईं आलिया

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने 2026 के स्वागत के मौके पर अपने फैंस के लिए कुछ बेहद खास पेश किया है। आलिया भट्ट की निजी जिंदगी की झलकियां आमतौर पर सोशल मीडिया पर बहुत कम दिखाई देती हैं, लेकिन जब भी वह कुछ पोस्ट करती हैं, तो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाता है। ऐसे ही इस बार उन्होंने नए साल की शुरुआत एक प्यारी फैमिली फोटो के साथ की, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है। आलिया ने रविवार को इंस्टाग्राम पर अपनी और परिवार की पहली तस्वीर पोस्ट की।

इस तस्वीर में वह समंदर के किनारे पति व अभिनेता रणबीर कपूर और बेटी राहा के साथ दिखाई दे रही हैं। बैकग्राउंड में सनसेट का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। तस्वीर में रणबीर अपनी बेटी राहा को हवा में उछालते नजर आ रहे हैं, जबकि आलिया उनके पीछे खड़ी मुस्कुराती हुई बेटी को देख रही हैं। इस छोटे से पल ने सोशल मीडिया पर फैंस को रोमांचित कर दिया। इस फोटो के साथ आलिया ने लिखा, आगे बढ़ते रहो आपज हैप्पी 2026।

आलिया के इस पोस्ट पर फैंस ने खूब प्यार लुटाया है। सोशल मीडिया यूजर्स ने रेड हार्ट इमोजी और कमेंट्स के जरिए अपनी खुशी जाहिर की। साल 2026 आलिया और रणबीर दोनों के लिए ही खास होने वाला है। आलिया जल्द ही अल्फा और लव एंड वॉर जैसी फिल्मों में नजर आएंगी। अल्फा एक जासूसी और एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें शरवरी वाघ और बॉबी देओल भी मुख्य भूमिका में हैं। वहीं संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में आलिया और रणबीर के साथ विक्की कौशल भी नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग और सेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। वहीं रणबीर कपूर इस साल पौराणिक फिल्म रामायण में भी नजर आएंगे। नितेश तिवारी निर्देशित यह फिल्म इस साल दीपावली पर रिलीज होने वाली है।

मैं खुद को सुंदर नहीं मानती, स्कूल में शेफाली शाह की होती थी बॉडी शेमिंग, हुमा की सलाह ने बढ़ाया हौसला

अभिनेत्री शेफाली शाह अपने अलग तरह के अभिनय के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में वो अपनी लोकप्रिय वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' के तीसरे सीजन में नजर आई थीं। उनके अभिनय की अक्सर तारीफहोती है। लेकिन शेफाली शाह का कहना है कि बचपन में अधिक खूबसूरत न होने के कारण उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ता था। लोग उन्हें तरह-तरह के ताने मारते थे। साथ ही उन्होंने हुमा कुरैशी की एक सलाह के बारे में भी बताया।

हाल ही में जूम के साथ बातचीत में शेफाली शाह ने बचपन में बुली किए जाने पर बात की है। अपनी शक्ल-सूरत को लेकर होने वाले भेदभाव के बारे में बात करते हुए शेफाली ने कहा कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं, मैं अपने माता-पिता की बात नहीं कर रही, बल्कि आम तौर पर आपको बताया जाता है कि आप सुंदर नहीं हैं। स्कूल में मुझे तंग किया जाता था। कोई मुझे पसंद नहीं करता था। एक लड़की थी जो मुझे बहुत मारती थी। वह मुझे 'तेलू' कहकर बुलाती थी। कुछ साल पहले मैं उससे उसके रेस्टोरेंट में मिली थी और मुझे उस पर तरस आया। फिर कोई जानने वाला कह देता कि अगर तुम पतली होतीं, तो बहुत अच्छी लगतीं। ऐसा बहुत कुछ होता है। लोग एक-दूसरे की सराहना नहीं करते। उनका मानना है कि अगर किसी को कोई चीज सुंदर या अच्छी लगे, तो उसे जरूर कहना चाहिए।

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि अगर कोई मेरे पास आकर मेरे बारे में कुछ अच्छा कहे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा पूरा दिन बन जाएगा। इसलिए अगर आपको कुछ अच्छा दिखे, तो कहिए। दूसरी बात यह है कि मुझे अपना रूप-रंग पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इतनी पतली हो पाऊंगी। बहुत कम ही ऐसा होता है जब मैं खुद को देखकर कहती हूं, 'ओह! मैं अच्छी लग रही हूं'। लेकिन मुझे ऐसा लगता ही नहीं। जब कोई मेरी तारीफ में कहता है, 'आप खूबसूरत लग रही हैं', तो मैं तारीफ को स्वीकार नहीं कर पाती।

शेफाली ने बताया कि अगर कोई मेरी तारीफ करता है तो मेरी पहली प्रतिक्रिया ये ही होती है कि मेरी मेकअप टीम कितनी बेहतरीन है। वे बहुत मेहनत करते हैं और मुझे खूबसूरत बनाते हैं, जो कि सच है। वो कड़ी मेहनत करते हैं और मुझे ऐसा दिखाते हैं। तारीफें स्वीकार करने पर हुमा कुरैशी द्वारा दी गई एक सलाह को भी शेफाली ने याद किया। उन्होंने कहा कि मुझे एक इंटरव्यू याद है जिसमें हुमा ने कहा था, 'शेफ यह तारीफ है। इसे स्वीकार करो। तारीफें स्वीकार करना सीखो।' इस दौरान अभिनेत्री ने स्वीकार किया कि कभी-कभी वह खुद को सहज महसूस नहीं करतीं। मुझे ज्यादातर समय ऐसा लगता है कि मैं काफी नहीं हूं। इसे देखने का एक तरीका यह है कि मेरा आत्मविश्वास कम है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो शेफाली शाह आखिरी बार पिछले साल रिलीज हुई अपनी लोकप्रिय वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' के तीसरे सीजन में नजर आई थीं। लड़कियों की तस्करी पर आधारित इस सीरीज में उनके साथ हुमा कुरैशी प्रमुख भूमिका में नजर आई थीं। हुमा सीरीज में निगेटिव रोल में हैं। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

सात समंदर पार भी सुरभि चंदना को सता रही मुंबई की याद, कहा- वापस लौटने का मन कर रहा है

मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि यहां रहने वालों के लिए एक एहसास है। जो एक बार मुंबई में रह लेता है, वह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, इस शहर की याद उसे खींच ही लाती है। कुछ ऐसा ही लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री सुरभि चंदना के साथ हुआ। सात समंदर पार विदेश यात्रा पर गई सुरभि अपने शहर और खासतौर पर मुंबई के मशहूर वड़ा पाव को याद कर इमोशनल हो उठी, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा की।

सुरभि चंदना ने रविवार को इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह पिछले 15 दिनों से देश से बाहर हैं और अब उन्हें मुंबई की छोटी-छोटी चीजों की बहुत याद आने लगी है। इस वीडियो में सुरभि ने मजेदार अंदाज में दिखाया कि कैसे विदेश की शानदार जगहों और सुविधाओं के बीच रहते हुए भी उनका दिल मुंबई के ट्रैफिक, वड़ा पाव और सड़कों के गड्ढों तक को मिस कर रहा है।

वीडियो में सुरभि ने साल 2006 में आई फिल्म शादी से पहले के एक मशहूर डायलॉग का इस्तेमाल किया। इस फिल्म में सुनील शेट्टी का किरदार अपने शहर के लिए तड़पता हुआ दिखता है, और उसी भावना को सुरभि ने मजेदार ट्विस्ट के साथ पेश किया।

वीडियो में वह कहती नजर आती कि अब उनका मन वापस मुंबई लौटने का कर रहा है, ताकि वह अपने शहर की रौनक और वहां की जिंदगी को फिर से जी सकें। वीडियो के ऊपर उन्होंने टेक्स्ट में लिखा, 15 दिन विदेश में बिताने के बाद अब मुंबई की असली पहचान याद आने लगी है। ट्रैफिक, वड़ा पाव और गड्ढे देखने की तलब लग रही है। सुरभि ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, च्च्मुंबई, वड़ा पाव, तेरी याद आ गई।

को-एक्टर्स से दोस्ती हो या न हो, अभिनय पर नहीं पड़ना चाहिए असर डायना पेंटी

इंडस्ट्री में कलाकारों को न सिर्फ अपने किरदार में ढलना पड़ता है, बल्कि निजी रिश्तों और भावनाओं से ऊपर उठकर काम करना भी सीखना होता है। एक अच्छा अभिनेता वही माना जाता है जो अपने सह-कलाकारों के साथ निजी समीकरण चाहे जैसे भी हों, कैमरे के सामने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ किरदार निभा सके। इसी सोच को लेकर अभिनेत्री डायना पेंटी ने बात की।

अपनी नई स्ट्रीमिंग सीरीज डू यू वाना पार्टनर के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अभिनय, प्रोफेशनलिज्म और को-एक्टर्स के साथ काम करने के अनुभव पर विस्तार से बात की। आईएएनएस से बात करते हुए डायना पेंटी ने कहा, एक अच्छे अभिनेता के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह निजी रिश्तों को अपने काम पर हावी न होने दे। चाहे आप किसी सह-कलाकार के साथ अच्छे दोस्त हों या नहीं, स्क्रीन पर जो दिखता है, वह पूरी तरह से किरदार की मांग पर आधारित होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत संबंधों पर।

डायना ने कहा, च्च्डू यू वाना पार्टनरज्ज में मेरी सह-कलाकार तमन्ना भाटिया हैं, और उनके साथ काम करने का अनुभव काफी अच्छा रहा। हम दोनों के बीच सेट पर अच्छी बॉन्डिंग बनी, लेकिन मेरा मानना है कि एक अभिनेता की असली परीक्षा यही होती है कि वह निजी रिश्तों से अलग रहकर अपने किरदार को कितनी सच्चाई से निभा पाता है। अभिनय की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि कलाकार अपने निजी अनुभवों और भावनाओं को कितनी समझदारी से अलग रख पाता है। डायना ने कहा, इस शो के मामले में मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं, क्योंकि तमन्ना के साथ मेरी दोस्ती स्वाभाविक रूप से बन गई थी। सेट पर माहौल काफी सहज और सकारात्मक था, जिससे काम करना और भी आसान हो गया। जब आपका रिश्ता ऑफ-स्क्रीन मजबूत होता है, तो वही मजबूती ऑन-स्क्रीन भी नजर आने लगती है। इससे सीन में एक अलग तरह की सच्चाई और ऊर्जा आ जाती है, जो दर्शकों को भी महसूस होती है।

तमन्ना भाटिया के साथ अपनी केमिस्ट्री पर बात करते हुए डायना ने कहा, हम दोनों को कभी भी एक-दूसरे के साथ तालमेल बैठाने में कोई परेशानी नहीं हुई। हमने कई सीन्स में साथ में काम किए और कई बार नए एक्सप्रेशन भी जोड़ पाए। जब कलाकार एक-दूसरे के साथ सहज होते हैं, तो इम्प्रोवाइज करने की आजादी भी मिलती है, जो कहानी को और बेहतर बना देती है। उन्होंने कहा, मैं और तमन्ना एक-दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल थे कि बिना झिझक अपनी राय रख सकते थे। हमारे बीच कोई औपचारिक भरा रिश्ता नहीं था, जहां हर बात सोच-समझकर कहनी पड़े। हम खुलकर एक-दूसरे से बात कर सकते थे, चाहे वह सीन से जुड़ी सलाह हो या किसी डायलॉग पर चर्चा। ऐसा माहौल हर प्रोजेक्ट में नहीं मिलता और जब मिलता है, तो कलाकारों के काम में उसका साफ असर दिखता है।

डायना ने कहा, कलाकारों की अच्छी बॉन्डिंग काम को आसान बना देती है, लेकिन एक अभिनेता को हर हाल में प्रोफेशनल रहना चाहिए। निजी रिश्ते कभी भी किरदार से बड़े नहीं होने चाहिए। अभिनय एक ऐसी कला है जिसमें अनुशासन और आत्म-नियंत्रण बहुत जरूरी है।

खास खबर

मुख्यमंत्री साय ने समाजसेविका पद्मश्री राजमोहिनी देवी की पुण्यतिथि पर किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सामाजिक चेतना और जनसेवा की सशक्त प्रतीक पद्मश्री राजमोहिनी देवी की 6 जनवरी को पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आदिवासी समाज से निकलकर सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करने वाली स्वर्गीय राजमोहिनी देवी का जीवन सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणादायी गाथा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजमोहिनी देवी ने विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के अधिकारों, स्वाभिमान और स्वावलंबन के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने नशाखोरी, कुप्रथाओं और शोषण के विरुद्ध जनजागरण को अपना ध्येय बनाया और समाज को जागरूक बनाने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वर्गीय राजमोहिनी देवी की निस्वार्थ सेवा, अदम्य साहस और लोकहित के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के लिए कार्य करने की निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। उनका जीवन और कृतित्व सदैव समाज के लिए पथप्रदर्शक बना रहेगा।

नगरीय प्रशासन विभाग ने आकांक्षी शौचालयों के निर्माण पूर्ण करने तय की समय-सीमा

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत विभिन्न नगरीय निकायों में स्वीकृत आकांक्षी शौचालयों के निर्माण पूर्ण करने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत प्रदेश के 78 नगरीय निकायों में 141 आकांक्षी शौचालय मंजूर किए गए हैं। इनमें से 26 शौचालयों के निर्माण पूर्ण हो गए हैं। निर्माणाधीन शौचालयों में से 28 प्लिंथ लेवल पर, 18 लिंटल लेवल पर और 55 रूफलेवल पर हैं। राज्य शासन ने इन शौचालयों के निर्माण जल्द पूर्ण करने संबंधित नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को मंत्रालय से परिपत्र जारी किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आकांक्षी शौचालयों के निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए जिन शौचालयों के काम रूफतक पहुंच गए हैं, उन्हें 31 जनवरी 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने लिंटल स्तर तक के निर्माण वाले शौचालयों के काम 28 फरवरी 2026 तक पूर्ण करने को कहा है।

जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनी आमजनों की समस्याएं, त्वरित राहत के दिए निर्देश

कोरबा। जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ दूरस्थ पहाड़ी, वनांचल क्षेत्रोंसे अपनी समस्याओं के समाधान की आस लेकर आए नागरिकों की परेशानियों को कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने गंभीरता से सुना। उन्होंने प्रत्येक शिकायत को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों की जांच कर शीघ्र एवं न्यायसंगत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में ग्रामीणजन धान विक्रय, रकबा संशोधन एवं त्रुटिपूर्ण गिरदावरी से संबंधित समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए खाद्य अधिकारी को धान उपार्जन मामलों की जांच कर वास्तविक हितग्राहियों को शीघ्र राहत देने तथा राजस्व अधिकारियों को गिरदावरी एवं रकबा प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए।

डीएसआईआर ने धमतरी जिले की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने एनआईटी को STREE परियोजना की स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने कहा- यह पहल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाकर सतत आजीविका के अवसर करेगी सृजित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण एवं विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर को STREE (महिलाओं की आर्थिक वृद्धि को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी संसाधनों के माध्यम से कौशल विकास) परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना की स्वीकृति का हस्ताक्षर समारोह 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह की गरिमामय उपस्थिति रही।

यह पहल एनआईटी रायपुर की कंपनी एनआईटी रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं उपयोग कार्यक्रम के तहत समर्थित इस परियोजना के लिए 36 माह की अवधि हेतु 90 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महिला कौशल उपग्रह केंद्रों की स्थापना करना है, जिसके माध्यम से तीन वर्षों में 300 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

एनआईटी रायपुर की ओर से इस परियोजना का मार्गदर्शन निदेशक डॉ. एन. वी. रामना राव द्वारा किया जा रहा है।परियोजना का नेतृत्व डॉ. अनुज कुमार शुक्ला, सहायक प्राध्यापक एवं प्रधान अन्वेषक कर रहे हैं। उनके साथ पवन कटारिया, सहायक कुलसचिव एवं सह-प्रधान अन्वेषक एवं प्रभारी अधिकारी, NITRRFIE के रूप में जुड़े हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की ओर से डॉ. विपिन शुक्ला, वैज्ञानिक-जी एवं सलाहकार तथा के प्रमुख, तथा डॉ. वंदना कालिया, वैज्ञानिक 'एफ' इस परियोजना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समारोह में डॉ. अनुज कुमार शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, एनआईटी रायपुर एवं स्ञ्जक्रश्वश्व परियोजना के प्रधान अन्वेषक उपस्थित थे, जो शिक्षा जगत, सरकार एवं जिला प्रशासन के बीच सुदृढ़ सहयोग का प्रतीक है।

STREE परियोजना ग्रामीण महिलाओं के समग्र कौशल विकास पर केंद्रित रहेगी। इसके अंतर्गत कोसा (कोकून) रेशम से फाइबर निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण, आधुनिक बुनाई तकनीकें, उत्पाद डिजाइन एवं विकास, उद्यमिता विकास कार्यक्रम तथा बाजार संपर्क सहायता जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पहल विशेष रूप से हाशिये पर बसे एवं कृषि-आधारित समुदायों को लक्षित करती है, जिसका उद्देश्य महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों का सृजन और सतत आजीविका के नए अवसर प्रदान करना है।

एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की विशिष्ट उपस्थिति में STREE परियोजना की स्वीकृति का समारोह समावेशी नवाचार और महिला सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एनआईटी रायपुर के लिए एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है। स्ञ्जक्रश्वश्व परियोजना ग्रामीण महिलाओं के लिए सतत और स्केलेबल समाधान बनाने हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को जमीनी स्तर के विकास के साथ एकीकृत करने की हमारी दृष्टि को साकार करती है।

मुख्यमंत्री साय ने इस परियोजना को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि STREE (Skill Development through Technological Resources for Empowering Economic Growth of Women) परियोजना का एनआईटी रायपुर को स्वीकृत होना छत्तीसगढ़, विशेषकर धमतरी जिले की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महिला कौशल उपग्रह केंद्रों की स्थापना तथा अगले तीन वर्षों में 300 ग्रामीण महिलाओं को कोसा रेशम फाइबर निष्कर्षण, आधुनिक बुनाई, उत्पाद डिजाइन, उद्यमिता और बाजार संपर्क जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर यह पहल महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों और सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देगी। यह परियोजना छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नेतृत्व में विकास और समावेशी प्रगति की हमारी दृष्टि के अनुरूप है।

समाज कल्याण की योजनाओं से लाखों जरूरतमंदों को मिला संबलः मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर । समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पिछले दो वर्षों में समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए व्यापक एवं प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, विधवा एवं परित्यक्त महिलाएं तथा उभयलिंगी व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत 22 लाख से अधिक हितग्राहियों को पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिनमें से अधिकांश को डीबीटी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड, छात्रवृत्ति, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण, विवाह प्रोत्साहन योजना और विशेष शिक्षण संस्थानों के माध्यम से हजारों दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से अब तक लाखों वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, विधवाओं एवं परित्यक्त महिलाओं को नि:शुल्क तीर्थ यात्रा कराई गई है।

प्रेस वार्ता में मंत्री राजवाड़े ने बताया कि नशामुक्ति, उभयलिंगी व्यक्तियों के सशक्तिकरण, वृद्धाश्रम संचालन, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुनर्वास तथा 'सियान हेल्पलाईन' जैसी पहलों से समाज के कमजोर वर्गों को सीधा लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और समाज कल्याण विभाग की योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री साय से राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव समिति ने की मुलाकात

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मंत्रालय महानदी भवन में राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव 2026 समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की।

कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव में मुख्य अतिथि के रुप में आमंत्रित किया। इस अवसर पर के.के. भारद्वाज, डॉ. संदीप जैन, नरेंद्र लोधी, गोविंद वर्मा, पुष्कर साहू, संतोष लोधी, अशोक चंद्राकर, देवनाथ साहु, राकेश सोनकर, हीरामन कोसले, विक्रम परमार, चंद्रशेखर साहू, गणेश राम साहू, दूजे राम धीवर उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से हरिशंकर पटेल की बदली तकदीर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ग्रामीण अंचलों में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। इस योजना का प्रभावी उदाहरण रायगढ़ विकासखंड के ग्राम कलमी निवासी हरिशंकर पटेल हैं, जिन्होंने शासन की योजना का लाभ उठाकर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की, बल्कि मछली पालन के क्षेत्र में एक सफल और आत्मनिर्भर मत्स्य कृषक के रूप में पहचान स्थापित की है। लगभग पाँच वर्षों से मत्स्य पालन से जुड़े श्री हरिशंकर पटेल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण योजना का लाभ लिया। उन्होंने अपनी निजी भूमि पर 0.607 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तालाब का निर्माण कर वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन की शुरुआत की। सामान्य वर्ग के मत्स्य कृषक होने के कारण उन्हें योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ, जिससे तालाब निर्माण एवं प्रारंभिक व्यवस्थाओं में उल्लेखनीय सहयोग मिला।

मत्स्य पालन विभाग द्वारा उन्हें रोहु, कतला एवं मृगल जैसी उन्नत प्रजातियों के मत्स्य बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए गए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्वयं के संसाधनों से पंगास और रूपचंदा मछली के बीज का संचयन भी किया, जिससे उत्पादन में विविधता आई और आय के नए अवसर सृजित हुए। श्री पटेल प्रतिवर्ष नवंबर से जनवरी के मध्य मत्स्याखेट करते हैं।

मंत्री नेताम ने 266 हितग्राहियों को डीबीटी से 31.92 लाख रुपये किए अंतरित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से गांव-गांव में स्वच्छता की एक नई जागरूकता आई है। अब प्रत्येक परिवार खुले में शौच से परहेज कर अपने सम्मान और स्वास्थ्य के लिए पक्के जलवाहित शौचालयों का नियमित उपयोग कर रहा है। इसी क्रम में आदिम जाति विकास मंत्री एवं कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने बटन दबाकर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत 266 हितग्राहियों को शौचालय निर्माण हेतु 31 लाख 92 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरित की।

प्रभारी मंत्री नेताम गत दिवस जिले में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। लाभान्वित हितग्राहियों में जनपद पंचायत सोनहत के 97 तथा जनपद पंचायत बैकुंठपुर के 169 हितग्राही शामिल हैं।

इस अवसर पर भारतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती रेणुका सिंह, कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा, उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जिले में स्वच्छता की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। शौचालय निर्माण से न केवल स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा मिला है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में पहुंचने से प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनी है।

वन मंत्री कश्यप ने 6 करोड़ 3 लाख 97 हजार रूपए के कार्यों का किया भूमिपूजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मुख्य आतिथ्य तथा बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप की अध्यक्षता में जिले के एक दिवसीय भ्रमण के दौरान छोटेडोंगर में भूमिपूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग, वन विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कुल 6 करोड़ 3 लाख 97 हजार रूपए की लागत वाले सात महत्वपूर्ण विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया।

मंत्री कश्यप के द्वारा किए गए भूमिपूजन कार्यों में विकासखंड नारायणपुर अंतर्गत धौड़ाई में हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण हेतु 1 करोड़ 21 लाख 16 हजार रुपये, चिपरेल नगर वन परियोजना के लिए 89 लाख 22 हजार रुपये तथा नवीन विश्रामगृह निर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ 1 लाख रुपए शामिल हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुकड़ाझोर-आकाबेड़ा मार्ग से ताड़ोनार तक सड़क निर्माण के लिए 85 लाख 93 हजार रूपए, कस्तुरमेटा-मोहंदी मार्ग से ब्रेहबेड़ा तक सड़क निर्माण हेतु 63 लाख 78 हजार रूपए, कस्तुरमेटा-मोहंदी मार्ग से मलकाल तक सड़क निर्माण कार्य के लिए 97 लाख 25 हजार रुपए तथा कस्तुरमेटा-मोहंदी मार्ग से मोहंदी गांव तक सड़क निर्माण हेतु 45 लाख 63 हजार रूपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। वन मंत्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और निश्चित ही यह क्षेत्र आने वाले समय में प्रदेश का एक समृद्ध एवं मॉडल क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। उन्होंने जानकारी दी कि ओरछा से नारायणपुर तक बनने वाली सड़क का निर्माण कार्य तीन चरणों में पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए टेंडर निरस्त किए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने छोटेडोंगर के हायर सेकेंडरी स्कूल में शेड निर्माण कराए जाने की भी घोषणा की।

बस्तर सांसद महेश कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को क्षेत्र में जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू कर विकास को गति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि डीएमएफ मद की राशि का उपयोग कर क्षेत्रीय विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।

मलेरिया रोकथाम पर संवाद से ही होंगे बेहतर हालात : कलेक्टर

श्रीकंचनपथ न्यूज

बीजापुर। कलेक्टर संबित मिश्रा के दिशा-निर्देश एवं जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे के मार्गदर्शन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.आर. पुजारी तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक विनोद कुमार साहू के नेतृत्व में जिला समन्वयक अशोक पाण्डेय एवं बीजादूतीर स्वयंसेवक मलेरिया मुक्त बीजापुर अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं।

बीजापुर जिला मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में से एक है। मलेरिया की रोकथाम को लेकर कलेक्टर संबित मिश्रा ने व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर देते हुए लोगों में व्यवहार परिवर्तन एवं सामाजिक बदलाव लाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने मलेरिया नियंत्रण एवं उन्मूलन के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मलेरिया के मामलों में कमी लाना एवं आमजन को इसके बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना है।

स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ, मितानिन प्रशिक्षक, मितानिन कार्यकर्ता एवं बीजादूतीर स्वयंसेवकों के समन्वय से जिले के लगभग 300 बीजादूतीर स्वयंसेवक मलेरिया की रोकथाम, लक्षण एवं उपचार संबंधी जानकारी जन-जन तक पहुँचा रहे हैं। मलेरिया से बचाव हेतु मच्छरदानी का उपयोग, घर-आसपास साफ-सफाई, गंदे पानी का जमाव न होने देना, पूरे ढके हुए कपड़े पहनना तथा बुखार या अन्य लक्षण होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर मलेरिया जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

CAR DECOR
House Of Exclusive
Seat Cover,
Car Stereos Matting &
Sun Control Film &
Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower.
Opp. Indian Coffee House,
Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM
Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES
FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden)
Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles,
CPVC Pipes &
Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

सरगुजा में तीन सड़क हादसों में तीन की मौत

सरगुजा। जिले में रविवार को नेशनल हाईवे-43 और आसपास के इलाकों में हुए तीन अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इन घटनाओं में दो बाइक सवार और एक राहगीर की जान चली गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। पुलिस ने तीनों मामलों में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहली घटना अंबिकापुर के नमनाकला क्षेत्र में मंगारी चौक के पास हुई। सीतापुर से अंबिकापुर लौट रहे चंद्रपाल दास (65) को एक महिंद्रा मालवाहक वाहन ने रॉन्ग साइड से आकर टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल चंद्रपाल दास को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दूसरी घटना नेशनल हाईवे-43 पर लालमाटी के पास ग्राम टिरंग में हुई। अंबिकापुर जा रहे दंपती इंद्रजीत पैकरा (22) और पुष्पा पैकरा (19) की बाइक को तेज रफ्तार अज्ञात चारपहिया वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में पुष्पा पैकरा की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि इंद्रजीत का उपचार जारी है। आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। तीसरी घटना लखनपुर थाना क्षेत्र के लहपटरा के पास हुई, जहां पैदल जा रहे आदिबल राम राजवाड़े (50) को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी भी जान नहीं बच सकी। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग हादसों की मुख्य वजह है। प्रशासन ने हाईवे पर निगरानी बढ़ाने और वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

ट्रक के ऊपर हाइटेंशन तार उठाते समय लगा करंट, युवक की हुई मौत

महासमुंद। जिले के सांकरा थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक बोरवेल गाड़ी के ऊपर चढ़कर बिजली का तार उठा रहे युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने मामले में वाहन चालक की लापरवाही को जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। सांकरा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक उमेश प्रसाद अगरिया (25), निवासी सिंगरौली (मध्यप्रदेश), एसएस बोरवेल्स की गाड़ी (केए 06 एमए 0869) में काम करता था। 3 दिसंबर को गाड़ी बोर खुदाई के लिए ग्राम लारीपुर जा रही थी। रास्ते में ग्राम बहादुरपुर के पास सड़क के ऊपर से 11 केवी की हाइटेंशन लाइन गुजरी थी, जिससे वाहन को निकलने में दिक्कत हो रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस जांच के अनुसार, ड्राइवर के कहने पर उमेश केबिन के ऊपर चढ़ा और डंडे के सहारे बिजली के तार को ऊपर उठाने लगा। इसी दौरान ड्राइवर ने अचानक गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, जिससे उमेश के हाथ में मौजूद डंडा टूट गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह सीधे हाइटेंशन तार की चपेट में आ गया और झुलसकर जमीन पर गिर पड़ा। गंभीर स्थिति में उमेश को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

छेड़खानी के आरोपी को छोड़ा, लोगों ने थाना घेरा

दंतेवाड़ा। बचेली थाना क्षेत्र में आदिवासी युवती से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस की कार्रवाई ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को आहत किया, बल्कि पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया। हालात ऐसे बने कि ग्रामीणों को रात 12 बजे तक थाने के बाहर धरने पर बैठना पड़ा, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। घटना 31 दिसंबर की है। आदिवासी युवती के साथ छेड़छाड़ की शिकायत उसके परिजनों ने बचेली थाने में दर्ज कराई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने के बजाय हल्की धाराएं लगाईं और आरोपी को थाने से ही छोड़ दिया।

शराब घोटाला मामले में निरंजन दास समेत 31 अधिकारियों की 38.21 करोड़ की संपत्ति कुर्क

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व आबकारी आयुक्त आईएएस निरंजन दास सहित 30 अन्य आबकारी अधिकारियों की 38.21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी के अनुसार इस घोटाले से राज्य के खजाने को 2,800 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

ईडी ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि रायपुर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत यह अस्थायी कुर्की की है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें आगे और भी बड़े खुलासों की संभावना जताई गई है।

कुर्क की गई संपत्तियों में कुल 78 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कीमत करीब 21.64 करोड़ रुपये बताई गई है। इनमें आलीशान बंगले, प्रीमियम कॉम्प्लेक्स में फ्लैट, व्यावसायिक दुकानें और बड़े पैमाने पर कृषि भूमि शामिल हैं। इसके अलावा 16.56 करोड़ रुपये मूल्य की 197 चल संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं, जिनमें उच्च मूल्य की सावधि जमा (एफडी), विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि, जीवन बीमा पॉलिसियां, इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड शामिल हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनीतिक संरक्षण से जुड़े एक आपराधिक सिंडिकेट ने आबकारी विभाग पर कब्जा कर लिया था। तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास और सीएसएमसीएल के तत्कालीन सीईओ अरुण पति त्रिपाठी ने मिलकर एक समानांतर आबकारी व्यवस्था संचालित की।

इस सिंडिकेट ने सरकारी दुकानों के जरिए अवैध देसी शराब के निर्माण और बिक्री के लिए तथाकथित पार्ट-बी योजना चलाई। नकली होलोग्राम और गैर-कानूनी बोतलों का इस्तेमाल कर शराब सीधे भट्टियों से दुकानों तक पहुंचाई जाती थी, जिसमें सरकारी गोदामों को पूरी तरह दरकिनार किया गया। यह सब आबकारी अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से किया गया।

जांच में यह भी सामने आया है कि पार्ट-बी शराब की बिक्री की अनुमति देने के बदले आबकारी अधिकारियों को प्रति मामले 140 रुपये का कमीशन दिया जाता था। अकेले निरंजन दास ने इस घोटाले से 18 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की। आरोप है कि उसे इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए हर महीने करीब 50 लाख रुपये की रिश्वत मिलती थी। कुल मिलाकर 31 आबकारी अधिकारियों ने 89.56 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय (पीओसी) हासिल की।

यह मामला रायपुर स्थित एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी के संज्ञान में आया। एफआईआर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। पुलिस जांच में शराब घोटाले से राज्य को भारी राजस्व नुकसान और आरोपियों को समानुपातिक लाभ मिलने की पुष्टि हुई है। ईडी का कहना है कि वर्तमान कुर्की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के राजस्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी किस तरह गहरी साजिश और भ्रष्टाचार में शामिल थे। जांच अभी जारी है।

शिक्षक की हत्या का खुलासा: सक्ती में पत्नी ने ही ले ली पति की जान

श्रीकंचनपथ न्यूज

सक्ती। डभरा थाना क्षेत्र में शिक्षक अनिल भार्गव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए उनकी पत्नी सीमा भार्गव को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि अनिल भार्गव की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि घरेलू विवाद के दौरान उनकी पत्नी के हाथों हुई थी।

आरोपी महिला को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार ठनगन गांव निवासी शिक्षक अनिल भार्गव कुछ दिन पहले अपने घर में मृत पाए गए थे। प्रारंभिक तौर पर मौत को सामान्य गिरने का मामला बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध बना दिया। रिपोर्ट में सीने में गंभीर चोट और अंदरूनी रक्तस्राव को मौत का कारण बताया गया।

इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी सीमा भार्गव से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि अनिल अक्सर शराब पीकर घर आते थे और विवाद व मारपीट करते थे। 18 दिसंबर 2025 की रात भी इसी तरह झगड़े के दौरान गुस्से में उसने पति को धक्का दे दिया, जिससे वे ऊंचे चबूतरे से गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने मामले को हादसा बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे भी जांच जारी है।

रायपुर के रामा-वर्ल्ड में मिली युवक की लाश: एक्सीडेंट से मौत की आशंका

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर के रामा वर्ल्ड कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। युवक झारखंड का रहने वाला था, वह मजदूरी करने के लिए रायपुर आया था। युवक के पैर में गंभीर चोट के निशान हैं। जिससे पुलिस आशंका जता रही है कि युवक की मौत एक्सीडेंट से हुई है। हालांकि इस बात की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद हो पाएगी।

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान शुभम राणा (25) निवासी देवघर झारखंड के रूप में हुई है। शुभम रामा वर्ल्ड स्थित स्वर्णभूमि कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में कारपेंटरी का काम करता था। वहीं बाकी मजदूरों के साथ रह रहा था।

जानकारी के अनुसार, शुभम बीती रात करीब 11 बजे से अपने कमरे से निकला था। अगले दिन जब अन्य मजदूरों ने उसकी आसपास तलाश की। तभी पास के ही निर्माणाधीन मकान के पास शुभम की लाश पड़ी मिली, जिसे देखकर साथी घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

घटना की खबर मिलते ही विधानसभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में मामला एक्सीडेंट का लग रहा है। शव पर चोट के निशान होने की बात सामने आई है, हालांकि पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है।

इधर, घटना की सूचना मिलते ही झारखंड से परिजन रायपुर पहुंचे। परिजनों का कहना है कि शुभम का किसी से कोई विवाद नहीं था और इस तरह उसकी मौत स्वाभाविक नहीं लगती। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है।

विधानसभा थाना पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और शुभम के साथ काम करने वाले साथियों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

प्रशासन की कार्रवाई जारी, 40 प्रकरणों में 2712.8 क्विंटल अवैध धान व 2 वाहन जप्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

अंबिकापुर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिले में अवैध धान संग्रहण, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सघन कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज जिले के विभिन्न तहसीलों में कुल 40 अवैध धान प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 2712.8 क्विंटल धान जप्त किया गया है। दौरान 2 वाहनों को भी जब्त किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसीलवार की गई कार्रवाई में मैनपाट में 2 प्रकरणों में 52 क्विंटल, सीतापुर में 2 प्रकरणों में 144 क्विंटल (1 वाहन जप्त), उदयपुर में 12 प्रकरणों में 486 क्विंटल, दरिमा में 6 प्रकरणों में 200 क्विंटल, अम्बिकापुर में 10 प्रकरणों में सर्वाधिक 1546.8 क्विंटल (1 वाहन जप्त), लखनपुर में 5 प्रकरणों में 230 क्विंटल, बतौली में 1 प्रकरण में 24 क्विंटल तथा लुण्ड्रा में 2 प्रकरणों में 30 क्विंटल अवैध धान जप्त किया गया है।

कलेक्टर अजीत वसंत ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए। उन्होंने ने सभी तहसीलों में राजस्व, खाद्य, सहकारिता एवं पुलिस विभाग के समन्वय से सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत संयुक्त टीम द्वारा औचक जांच, नाकाबंदी एवं सत्यापन कार्यवाही की जा रही है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही धान का विक्रय करें तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में संलिप्त होने से बचें।

3 लाख की चोरी, नाबालिग-खरीदार समेत 4 गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

अंबिकापुर। शहर के नवापारा स्थित एक सूने मकान में चोरी हो गई। परिवार 25 दिसंबर से बाहर गया था और 2 जनवरी को वृंदावन से घर लौटे तो चोरी का पता चला। सूचना पर गांधीनगर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर प्रकरण का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 3 लाख का चोरी का सामान बरामद किया है।

आरोपियों में एक नाबालिग और एक दुकानदार है। पुलिस ने बताया मामले में मकान मालिक नवापारा निवासी ज्योति गोस्वामी ने 2 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थीं। पुलिस को जांच के दौरान

संदेही शिवम रवि के बारे में पता चला। शिवम से पूछताछ करने पर अपने दो साथियों विलसन मिंज और एक नाबालिग के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों ने चोरी किया सोने का हार नवापारा स्थित एक ज्वेलर्स अंकित सोनी को बेचा था। आरोपियों से 35 हजार नकद, सोना-चांदी के जेवरात, गलाया हुआ सोना और घटना में प्रयुक्त लोहे की छड़ जब्त की गई।

रेलवे ब्रिज से गिरे दो युवक, लोको पायलट की सूझबूझ से बची जान

श्रीकंचनपथ न्यूज

बालोद । बालोद जिले में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र के रेलवे ब्रिज पर बाइक सवार दो युवक अनियंत्रित होकर करीब 40 फीट नीचे रेलवे पटरी पर गिर पड़े। इसी दौरान ट्रैक पर आ रही मालगाड़ी के लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर दोनों की जान बचा ली।

जानकारी के अनुसार, रेलवे ब्रिज से गिरने के बाद एक युवक सीधे रेल पटरी पर जा गिरा, जबकि दूसरा पास की नाली में भरे पानी में गिर गया।

हादसे में दोनों युवकों के पैर टूट गए और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी समय उसी ट्रैक पर एक मालगाड़ी आ रही थी। लोको पायलट ने युवकों को नीचे गिरते देखा और बिना देर किए इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। ट्रेन कुछ ही दूरी पर रुक गई।

इसके बाद लोको पायलट मौके पर पहुंचा, जहां दोनों युवक दर्द से कराहते हुए मदद की गुहार लगा रहे थे। लोको पायलट के अनुसार, घायल युवक बार-बार कह रहे थे कि प्लीज उठा दो, मेरे दोनों पैर टूट गए हैं, बाहर निकाल दो, मम्मी को फेन करना है। इसके बाद लोको पायलट ने तत्काल 112 पर कॉल कर एंबुलेंस की सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस और 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोको पायलट की सतर्कता और मानवीय संवेदनशीलता की जमकर सराहना की जा रही है।

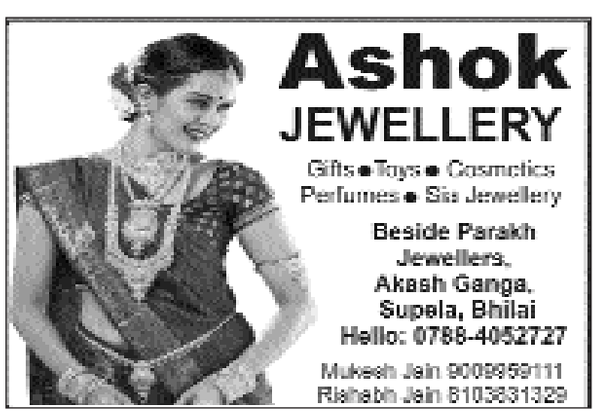

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

जनादेश परब

विश्वास गौरव निर्माण

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

2 साल निरंतर सेवा निरंतर विकास

उद्यम क्रांति योजना

युवाओं को स्वरोजगार के लिए
50% सब्सिडी पर ब्याजमुक्त ऋण

RO-45320/5

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950